मासिक पत्रिका RAJHIN/2007/21229 वर्ष-01, अंक नं. 07

जयपुर टाइम्स

राजस्थान की रग-रग से निकली बात जयपुर टाइम्स मैग्जीन के साथ

भजनलाल शर्मा की लाजवाब वर्किंग 04

भजनलाल शर्मा की लाजवाब वर्किंग स्टाइल

जमीन से जुड़े नेता का जमीन से जुड़ा 11

जमीन से जुड़े नेता का जमीन से जुड़ा ऐतिहासिक जन्मदिन समारोह

प्रशासनिक व्यववस्था का स्वर्णिम अध्याय 16

प्रशासनिक व्यवस्था का स्वर्णिम अध्याय लिखने की काबिलियत रखते हैं वी श्रीनिवास

कांग्रेस में जूली की ऊंची उड़ान, प्रतिपक्ष के 23

कांग्रेस में जूली की ऊंची उड़ान, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में खुद को साबित किया

पिता के पद चिह्न पर बेटी 31

पिता के पद चिह्न पर बेटी, मंडावा को किया रोशन, हाई कमान ने दी बड़ी जिम्मेदारी

विराटनगर को अपराध और बेरोजगारी 38

विराट नगर को अपराध और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने में जुटे कुलदीप धनकड़

सचिन की पुलिस कमिश्नरेट में दूसरी 43

सचिन की पुलिस कमिश्नरेट में दूसरी पारी का शानदार आगाज

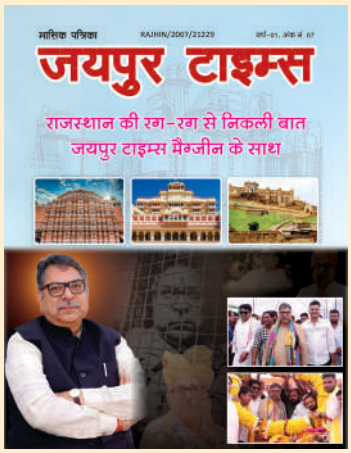

प्रकाशक, मुद्रक
रामेश्वर लाल जाट

संपादक
नीतू चौधरी

उप संपादक
कुमकुम रंगा, रूपचंद गुर्जर, रोहित शर्मा

ग्राफिक डिजाईनर
रजत जाखड़

स्वत्वाधिकारी

केम्ब्रिज मल्टी मीडिया के लिए प्रकाशक, मुद्रक रामेश्वरलाल जाट द्वारा केम्ब्रिज मल्टी मीडिया प्रा.लि. सी-565, सी-4सी स्कीम, न्यू लोहा मण्डी रोड़, सीकर रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं सी-565, सी-4सी स्कीम, न्यू लोहा मण्डी रोड़, सीकर रोड़ जयपुर से प्रकाशित

संपर्क
संपादक
जयपुर टाइम्स (मासिक)
सी-588, सी-4सी स्कीम,
न्यू लोहा मण्डी रोड़
जयपुर-302013

E-mail
jaipurtimes2007@gmail.com

website
www.jaipurtimes.org

मो. 7014217770

मूल्य:- 100/- प्रति अंक
वार्षिक सदस्यता- 1251 (पोस्टल चार्ज सहित)

सुधी पाठकों के लिए जयपुर टाइम्स का विशेष संदेश

प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन

निवेश, विश्वास और भविष्य की नई इबारत!

प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। इसे ऐतिहासिक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस सम्मेलन ने न सिर्फ राज्य में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया, बल्कि वर्षों से प्रवासी राजस्थानी समाज के मन में मौजूद कई शंकाओं और प्रश्नों का भी समाधान किया। यह सम्मेलन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बेहतरीन प्रशासनिक कार्यकुशलता, मजबूत इरादों और दमदार व्यक्तित्व का जीता जागता उदाहरण है।

राजस्थान ऐसा राज्य है, जिसकी पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी अपने साथ मेहनत, उद्यमिता और संस्कृति की समृद्ध परंपरा लेकर चलते हैं। व्यापार, उद्योग, सेवा, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानियों ने जो मुकाम हासिल किया है, वह राज्य के लिए गर्व का विषय है। ऐसे में सरकार और प्रवासी समाज के बीच संवाद का यह मंच अत्यंत आवश्यक था।

पिछली कोशिशों से आगे का कदम

यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किए गए थे। उन आयोजनों का उद्देश्य भी निवेश आकर्षित करना और प्रवासियों को राज्य से जोड़ना था, लेकिन अक्सर वे औपचारिकता तक सीमित रह गए। घोषणाएं हुईं, मंच सजे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव दिखाई नहीं दिया। इस बार के सम्मेलन को अलग बनाने वाली बात यह रही कि सरकार ने केवल निवेश के आंकड़ों और भाषणों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रवासियों की व्यावहारिक समस्याओं, उनकी आशंकाओं और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नेतृत्व इस सम्मेलन की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा। उनके वक्तव्यों और संवाद में यह स्पष्ट झलका कि सरकार प्रवासियों को केवल निवेशक के रूप में नहीं, बल्कि राजस्थान के साझेदार के रूप में देख रही है। यही दृष्टिकोण इस सम्मेलन को सार्थक बनाता है।

निवेश से आगे विश्वास का निर्माण

निवेश किसी भी राज्य के विकास का आधार होता है, लेकिन निवेश तभी आता है जब विश्वास हो। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि राजस्थान अब निवेश के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण वाला राज्य बन रहा है। भूमि आवंटन, उद्योग स्थापना, अनुमतियों की प्रक्रिया, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सहयोग जैसे विषयों पर सरकार की स्पष्टता ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।

सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि सरकार ने प्रवासियों की शिकायतों और अनुभवों को खुले मंच पर सुना। कई प्रवासी उद्यमियों ने पिछली कठिनाइयों, फाइलों में उलझने, लालफीताशाही और स्थानीय स्तर पर सहयोग की कमी जैसे मुद्दों को उठाया। इन सवालों पर सरकार का सकारात्मक और समाधान-केन्द्रित रुख यह संकेत देता है कि अब केवल 'निवेश बुलाने' की नहीं, बल्कि 'निवेश को बनाए रखने' की सोच पर काम हो रहा है।

प्रवासी राजस्थानियों की भावनात्मक भागीदारी

प्रवासी राजस्थानी केवल पूंजी लेकर नहीं आते, वे अपने साथ राज्य के प्रति भावनात्मक जुड़ाव भी लाते हैं। सम्मेलन में यह भावनात्मक पक्ष भी पूरी मजबूती से सामने आया। अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की भावना, संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक विकास में योगदान देने की इच्छा-ये सभी पहलू इस आयोजन में दिखाई दिए।

सरकार के लिए यह एक अवसर है कि वह इस भावनात्मक जुड़ाव को योजनाबद्ध तरीके से राज्य के विकास से जोड़े। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी से विकास की गति को नई रफ्तार मिल सकती है।

दूरगामी परिणामों की उम्मीद

इस सम्मेलन की सफलता का असली मूल्यांकन आने वाले वर्षों में होगा। निवेश प्रस्ताव कितने ज़मीन पर उतरते हैं, कितने उद्योग स्थापित होते हैं, कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है-ये सभी प्रश्न भविष्य तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस सम्मेलन ने एक सकारात्मक शुरुआत की है।

अगर सरकार सम्मेलन में किए गए वादों और आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से लागू करती है, यदि प्रशासनिक स्तर पर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, और यदि निवेशकों को निरंतर सहयोग मिलता है, तो इसके दूरगामी परिणाम राजस्थान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।

चुनौती भी कम नहीं

हालांकि उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। निवेश के अनुकूल माहौल बनाए रखना, नौकरशाही में सुधार, स्थानीय स्तर पर विरोध की संभावनाओं को संतुलित करना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना-ये सभी पहलू सरकार की परीक्षा लेंगे। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि विकास केवल बड़े शहरों और चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रहे। प्रवासी निवेश को ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक ले जाना, वहां रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास करना ही इस सम्मेलन की वास्तविक सफलता होगी। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन ने राजस्थान के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी है। यह सम्मेलन केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं रहा, बल्कि सरकार और प्रवासी समाज के बीच विश्वास, संवाद और साझेदारी का सेतु बना। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्मेलन को एक बार की घटना न मानकर एक सतत प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया जाए। यदि सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर खरी उतरती है, तो यह सम्मेलन आने वाले समय में राजस्थान के आर्थिक पुनर्जागरण और समावेशी विकास का मील का पत्थर साबित हो सकता है।

-प्रधान संपादक
रामेश्वरलाल जाट

भजनलाल शर्मा की लाजवाब वर्किंग स्टाइल

राइजिंग राजस्थान को साल भर हुआ नहीं, फिर भी करीब 750000 लाख करोड़ के समझौते आए धरातल पर। राजस्थान के रेगिस्तान में भी बन रहा उद्योगों का नया माहौल। प्रदेश के आर्थिक विकास को मिली नई ताकत, बेरोजगारी की समस्या भी हो रही है तेजी से हल।

प्रदेश में पहली बार मेट्रो की रफ्तार से धरातल पर आ रहे समझौते

जयपुर। प्रदेश में भजनलाल सरकार के दौरान राइजिंग राजस्थान के आयोजन हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन इस आयोजन में हुए 35 लाख करोड़ के समझौते में करीब 750000 लाख करोड़ के समझौते धरातल पर आ गए हैं। इसे साधारण उपलब्धि नहीं मान सकते, क्योंकि अब से पहले भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इस तरह के कई बड़े-बड़े आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संस्थानों से जुड़े बड़े-बड़े लोग आए और निवेश के समझौते भी खूब हुए। लेकिन अधिकांश समझौते सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर ही रह गए, धरातल पर नजर नहीं आए। गिने-चुने समझौते ही धरातल पर आए, जिसकी वजह से प्रदेश में उद्योगों का अच्छा माहौल कायम नहीं हो सका। लेकिन इस बार राइजिंग राजस्थान आयोजन के कुछ ही महीनों में जिस तरह से बड़े पैमाने पर समझौते फाइलों से निकलकर धरातल पर आए हैं और सरकार ने निवेशकों को उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें निवेश का अच्छा प्लेटफार्म और जमीन उपलब्ध करवा रही है, उसे देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि भजनलाल सरकार अपने बाकी के कार्यकाल में जो समझौते पूरे होने को बचे हैं, उनमें अधिकांश समझौते धरातल पर उतारने में कामयाब हो सकती है। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान में हुए समझौते के क्रियान्वयन के लिए जो कार्य योजना और रणनीति तैयार की, उससे प्रभावित होकर राइजिंग राजस्थान में समझौते करने वाले उद्योगपति हकीकत में अपनी नई औद्योगिक इकाइयों और संस्थाओं को जमीन पर लाने की दिशा में तेजी से कार्य करते हुए दिख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब तक 750000 लाख करोड़ के समझौते धरातल पर आ गए। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में सबसे पहले जितनी बार भी आयोजन हुए, उनमें किए गए समझौते में मुश्किल से 10 से 15 प्रतिशत समझौते ही धरातल पर आए। लेकिन इस बार यह 10 प्रतिशत की उपलब्धि तो प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 1 साल पूरा होने से पहले ही हासिल कर ली है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बाकी के भजनलाल सरकार के कार्यकाल में 70 प्रतिशत समझौते धरातल पर आ सकते हैं। अगर इतने समझौते राजस्थान की जमीन पर उतर गए, तो फिर समझो राजस्थान की बल्ले बल्ले।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चतुर और कुशल नीति से आ रहे अच्छे परिणाम

अब से पहले चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की, हर पार्टी की सरकार ने देश और विदेश के निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के क्रम में कभी भी अपने शासनकाल के पहले साल में इस तरह का आयोजन नहीं करवाया। सरकारों ने इस तरह के आयोजन अपने शासनकाल के तीसरे या चौथे या आखिरी साल में करवाया, जिसकी वजह से इस तरह के सम्मेलन में आयोजित किए गए अधिकांश समझौते धरातल पर उतर ही नहीं पाए। इसके कई बड़े कारण रहे, जिसमें एक बड़ा कारण यह भी रहा की सरकारों को इतने व्यापक स्तर पर हुए समझौते के धरातल पर लाने के लिए पूरा समय ही नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकारों ने अपने कार्यकाल के अंतिम सालों में इस तरह का आयोजन करवाया। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने शासनकाल के पहले ही कार्यकाल में राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा कार्यक्रम सफलतापूर्वक तो आयोजित करवाया ही, इसके अलावा इस सम्मेलन में व्यापक स्तर पर किए गए सभी समझौते को धरातल पर लाने के लिए एक ठोस मजबूत कार्य योजना तैयार की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भले ही पहली बार के विधायक हो और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन अनुभव और कुशल कार्य योजना तैयार करने में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन यही सोचकर करवाया कि इस सम्मेलन में होने वाले समझौते के क्रियान्वन के लिए उनके पास पूरा समय होगा, जिसकी वजह से अन्य सरकारों की तरह यह आयोजन सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल के पहले ही कार्यकाल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करवाया, जिसमें 35 लाख करोड़ के समझौते विभिन्न क्षेत्रों में हुए। भजनलाल शर्मा यह भी जानते थे कि भले ही 35 लाख करोड़ के समझौते हो गए हो, लेकिन जब तक यह समझौते धरातल पर नहीं आएंगे, तब तक इनका कोई औचित्य और फायदा भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने राइजिंग राजस्थान में हुए समझौता के क्रियान्वयन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना ही कर दी, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा कर्मठ और अनुभवी आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया और उन्हें अलग-अलग डिपार्मेंटों और क्षेत्र से संबंधित समझौते के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की। और फिर इन सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया कि हर स्तर पर चाहे कुछ भी हो, जिस किसी ने भी राइजिंग राजस्थान में समझौता किया है, उसे अपना समझौता पूरा करने के लिए कहा जाए, उससे नियमित रूप से बातचीत की जाए और बराबर संवाद कायम किया जाए, तथा उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप निवेश के लिए कहा जाए। उनकी जो समस्याएं हो उनका समाधान किया जाए और उन्हें किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अधिकारी खुद उनसे नियमित रूप से बातचीत करता रहे और सरकार की ओर से निवेशकों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं, उनके बारे में भी उन्हें बारीकी से और गंभीरता से बताया जाए। जिसकी वजह से जिस जिस अधिकारी को राइजिंग राजस्थान के समझौते की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने इस पूरे कार्य को काफी गंभीरता से लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उनसे नियमित रूप से उनके कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। यही वजह है कि अधिकारी भी राइजिंग राजस्थान के समझौता के क्रियान्वयन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि कुछ ही महीना में बड़ी संख्या में समझौते धरातल पर आ गए।

भजनलाल शर्मा कभी मुख्य सचिव से तो कभी खुद अधिकारियों से ले रहे हैं फीडबैक

राइजिंग राजस्थान में हुए समझौता के क्रियान्वयन के बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले दिन से ही काफी गंभीर और अलर्ट बोर्ड पर नजर आए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा इन समझौते के सफल क्रियान्वयन के लिए खुद नियमित रूप से समझौते के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेते रहते हैं। मुख्यमंत्री शर्मा कभी मुख्य सचिव से इन समझौते के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट लेते रहते हैं, तो कभी खुद सामूहिक रूप से अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करके उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री शर्मा ने समझौते के क्रियान्वयन के लिए अलग से विभाग की ही स्थापना की और फिर इस डिपार्टमेंट से दो दर्जन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जोड़ा और इन अधिकारियों को अलग-अलग सेक्टर और अलग-अलग विभागों से जुड़े समझौते के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया। जब तक प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर सुधांशु नियुक्त रहे, तब तक मुख्यमंत्री शर्मा उनसे नियमित रूप से राइजिंग राजस्थान के समझौते के क्रियान्वयन की पूरी रिपोर्ट लेते रहे। किस-किस ने किस-किस क्षेत्र में निवेश के लिए एप्लीकेशन लगाई है, किस-किस की एप्लीकेशन पर सरकार की ओर से कितनी करवाई हो चुकी है, किस एप्लीकेशन के क्रियान्वयन में किस बात के लिए अड़चन आ रही है, निवेश करने वाले के सामने क्या तकलीफ है, कितने को जमीन का आवंटन हुआ, इत्यादि के बारे में मुख्यमंत्री शर्मा नियमित रूप से फीडबैक ले रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के समझौता के क्रियान्वयन के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव सुधांशु भी काफी गंभीर और एक्टिव रहे और अब नए मुख्य सचिव श्रीनिवास भी राइजिंग राजस्थान के समझौता के क्रियान्वयन के लिए पूरे जोश, उत्साह और नवाचार के साथ कार्य कर रहे हैं। जानकार लोगों का कहना है कि पिछली सरकारों में इस तरह के सम्मेलन में समझौते तो बहुत हुए, लेकिन समझौते होने के बाद उनके क्रियान्वयन को लेकर पिछली सरकारों ने भी ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई और ना ही निवेश करने वालों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं और कदम उठाए। जिसकी वजह से देश और विदेश से आए मेहमानों ने सम्मेलन में समझौते तो सरकार को खुश करने के लिए खूब किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर तत्कालीन सरकारों की ओर से भजनलाल सरकार की तरह समझौता करने वाले प्रत्येक मेहमान से नियमित संवाद रखा जाता और उनसे नियमित बातचीत का सिलसिला रखा जाता और उन्हें हर तरह से भरोसे में लिए जाने का प्रयास किया जाता, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों को भी इस कार्य में सफलता मिलती। लेकिन पिछली सरकारों ने अपने शासनकाल के अंतिम सालों में इस तरह का आयोजन किया, जिसकी वजह से उन्होंने समझौता करने वाले मेहमान के भरोसे पूरा समझौता छोड़ दिया। सरकार ने आगे बढ़कर ठोस पहल नहीं की, जिसकी वजह से समझौता करने वाले मेहमान ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन भजनलाल सरकार समझौता करने वाले प्रत्येक मेहमान से न केवल निवेश के लिए बातचीत कर रही है, बल्कि उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें भरोसा भी दिला रही है कि उन्हें राजस्थान में निवेश करने से जितना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट और कहीं नहीं होगा। इसके अलावा सरकार उन्हें हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नियमित रूप से संबंधित अधिकारियों से बैठक करते हैं और फिर उनसे एक-एक समझौते के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर बात करते हैं। इस दौरान निवेश करने वाली मेहमान के सामने कोई तकलीफ आती है, तो उसका निदान भी करते हैं।

सौर ऊर्जा में व्यापक तौर पर हुए समझौते, सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले नंबर पर राजस्थान

सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में नंबर वन की पोजीशन पर है। राजस्थान के रेतीले जिले सौर ऊर्जा उत्पादन का बड़ा स्त्रोत बने हुए हैं और प्रदेश की भजनलाल सरकार ने भी सौर ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं और कई बड़ी नई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जिसकी वजह से प्रदेश सौर ऊर्जा के उत्पादन में पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस क्षेत्र में राइजिंग राजस्थान में बड़ी संख्या में समझौते भी हुए हैं, जिनका क्रियान्वयन भी तेजी से हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में बहुत जल्दी ही बिजली उत्पादन में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने वाला है, जिसके फल स्वरुप राजस्थान के बिजली के उपभोक्ताओं को समुचित बिजली तो मिलेगी ही, इसके अलावा प्रदेश के सभी किसानों को दिन में बिजली भी बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, क्योंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो राइजिंग राजस्थान में समझौते हुए थे, वे समझौते तेजी से जमीन पर उतर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र

में आने वाले कुछ ही सालों में क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जो राजस्थान के बिजली उत्पादन के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वैसे राजस्थान में पर्यटन, ऑटोमोबाइल, खनन, शिक्षा, चिकित्सा, स्टोन इत्यादि क्षेत्रों में राइजिंग राजस्थान में बड़ी संख्या में समझौते हुए हैं, जो तेजी से धरातल पर भी आ रहे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश और विदेश के उद्योगपति निवेश के लिए ज्यादा आतुर दिख रहे हैं। जानकार लोगों का कहना था कि एक समय ऐसा भी था जब राजस्थान में पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाएं अच्छी तरह से नहीं देख कर देश और विदेश के उद्योगपति यहां अपना उपक्रम और फैक्ट्री खोलने को राजी नहीं होते थे, लेकिन आज राजस्थान दुनिया भर के उद्योगपतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। जिसकी झलक राइजिंग राजस्थान में भी देखने को मिली, जब इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ समझौते हुए और समझौते ही नहीं हुई, बल्कि यह समझौते धरातल पर निरंतर तेजी से आ रहे हैं। वजह यही है कि आज राजस्थान हिंदुस्तान में नई फैक्ट्री खोलने का एक अच्छा स्थान बन गया है। यहां पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, वायु यातायात, बिजली, सुरक्षा, सभी क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, उसकी वजह से दुनिया भर के उद्योगपतियों की निगाह राजस्थान पर टिक गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान में जो यह नया बदलाव आया है, इस नए बदलाव की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम ने पिछले दो साल में जो कड़ी मेहनत की है, कई विदेश यात्राएं मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने की है, उसी का नतीजा है कि दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद कई बड़े उद्योगपति अब राजस्थान में निवेश के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहे देश हो या विदेश, जहां भी जाते हैं उद्योगपतियों को एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान में सिर्फ पर्यटन ही नहीं, बल्कि यहां हर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान में 85 से ज्यादा अलग-अलग तरह के खनन है, जिसमें निवेश करके मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान उद्योगपतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।

टाटा, बिरला, अडानी अंबानी और अनिल अग्रवाल जैसे बड़े उद्योगपतियों को दिल से भा गया राजस्थान

भजनलाल सरकार की राजस्थान में औद्योगिक माहौल स्थापित करने के लिए शुरू की गई नई व्यवस्थाएं और ठोस पहल ने देश और दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपतियों और औद्योगिक समूह से जुड़े लोगों का भरोसा और विश्वास हासिल कर लिया है। यही वजह है कि राइजिंग राजस्थान में गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला जैसे कई बड़े दिग्गज उद्योगपति नजर आए और इन्होंने यहां पर कई क्षेत्रों में समझौते भी किये और यह समझौते धरातल पर भी तेजी से उतर रहे हैं। वजह यही है कि इस बार भजनलाल सरकार विजन के तौर पर राइजिंग राजस्थान के समझौता को लिया है और दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक समझौते को पूरा करने के प्रयास में युद्ध स्तर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं, आने वाले 3 साल प्रदेश में औद्योगिक माहौल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि जिस स्फूर्ति और जिस तन्मयता के साथ राइजिंग राजस्थान के समझौता के क्रियान्वयन में यहां के ऑफिसर और सरकार दोनों जुटे हैं, उससे समझौते करने वाले देश और विदेश के उद्योगपतियों को भी अब यह एहसास हो गया है कि राजस्थान सरकार इस बार उन्हें इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। सरकार उन्हें हर हाल में राजस्थान से जोड़कर ही रहेगी। जानकार लोगों का कहना है कि देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों के मूवमेंट से राजस्थान को काफी फायदा होगा। राजस्थान की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, तो राजस्थान में विकास की रफ्तार और तेज होगी। एक तरफ जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो दूसरी तरफ प्रदेश में आधारभूत सुविधा का विस्तार भी तेजी से होना सुनिश्चित है, क्योंकि सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, जहां पर देश और दुनिया के उद्योगपति अपनी फैक्ट्री और उपक्रम खोल सकेंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही अन्य सुविधाओं का विस्तार होना भी निश्चित है। इसलिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों की राजस्थान में सक्रियता और उनकी गतिशीलता से निश्चित रूप से राजस्थान उद्योगों के मामले में अब तेजी से आगे बढ़ेगा। यह कटु सत्य है कि औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से अब तक पिछड़ रहा, लेकिन अब जिस तरह से भजनलाल सरकार ने विजन के तौर पर राजस्थान में औद्योगिक माहौल खड़ा करने की दिशा में कार्य कर रही है और उसके अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से आने वाले साल राजस्थान की पब्लिक और राजस्थान की सरकार दोनों के लिए काफी अच्छे साबित होते दिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राइजिंग राजस्थान से जुड़ी विदेश यात्राएं काफी असरदार साबित हुई

देश और विदेश के उद्योगपतियों को पसंद आ रही राजस्थान सरकार की योजनाएं और छूट

प्रदेश की भजन लाल सरकार ने देश और विदेश के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए कई तरह की सुविधा भी दी है। एक तरफ जहां निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की गई है, तो दूसरी तरफ रोजगार प्रोत्साहन योजना, टैक्स में छूट, सब्सिडी, उद्योगपतियों के लिए एकल खिड़की योजना, राइजिंग राजस्थान के समझौता के क्रियान्वयन के लिए एक अलग से ही विभाग की स्थापना करना, जिसमें 23 अनुभवी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करना, राज निवेश प्लेटफार्म द्वारा निवेश प्रक्रिया का डिजिटल करण और अनुमोदन का सरलीकरण जैसे कई बड़े नए कदम उठाए हैं। जिसकी वजह से यहां फैक्ट्री स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को एप्लीकेशन सबमिट करने से लेकर उन्हें जमीन आवंटन करने तक किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा। इस दौरान अगर कोई समस्या और दुविधा सामने आती भी है, तो सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों का सहयोग कर रही है। यही वजह है कि राइजिंग राजस्थान के समझौते तेजी से धरातल पर आ रहे हैं। सरकार जमीन आवंटन में भी उद्योगपतियों को ज्यादा चक्कर नहीं कटा रही।

जानकार लोगों का कहना है कि राइजिंग राजस्थान के आयोजन से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुनिया के कई देशों की यात्रा की थी। इन यात्राओं के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने विदेश में रहने वाले प्रमुख उद्योगपतियों और प्रमुख कारोबारियों से मुलाकात करके उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से निवेश करने वालों के लिए शुरू की गई विशेष सुविधाओं और योजनाओं के बारे में तो गंभीरता से जानकारी दी। इसके अलावा विदेश में रह रहे उद्योगपतियों को यह भी बताया कि वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और राजस्थान में उनका पैसा उनके कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाएगा और उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन सब के बारे में विदेश में रह रहे उद्योगपतियों को बहुत ही तथ्यात्मक और प्रभावशाली तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी, जापान, दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन और कई अन्य देशों की यात्राएं करके वहां के प्रमुख उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश के लिए राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इन विदेश यात्राओं के दौरान ही दुनिया भर के उद्योगपतियों को यह पता चल गया था कि राजस्थान में अब पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, चिकित्सा, सुरक्षा, सभी क्षेत्र में काफी अच्छा वातावरण बना हुआ है, इसलिए इन्वेस्ट के लिहाज से राजस्थान अच्छा प्रदेश है। बाद में राइजिंग राजस्थान के दौरान जब दुनिया भर के उद्योगपति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभिन्न कारोबार से जुड़े लोग यहां आए, तो उन्होंने राजस्थान में अपनी आंखों से हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव भी देखा। इसलिए इस बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ 35 लाख करोड़ के समझौते हुए और अब उनका क्रियान्वयन भी तेजी से हो रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि जब तक आप अपनी नई व्यवस्थाओं और नई योजनाओं के बारे में दुनिया को नहीं बताओगे, तब तक दुनिया कैसे आप पर भरोसा करोगी? इसीलिए मुख्यमंत्री शर्मा ने खुद कई देशों की यात्राएं करके वहां रह रहे उद्योगपतियों को राजस्थान सरकार की योजनाओं और व्यवस्थाओं के बारे में गंभीरता से जानकारी दी। उद्योगपतियों को भी यह लगा कि जब एक प्रदेश का मुखिया उन्हें इतना भरोसा दिला रहा है, तो हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए इस बार समझौते तेजी से जमीन पर आ रहे हैं।

भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सभी इलाकों में व्यापक तौर पर औद्योगिक क्षेत्र किए विकसित

प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में हुए समझौते की क्रियान्वयन और प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह को देखते हुए प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए हैं, ताकि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में औद्योगिक वातावरण स्थापित करने में संतुलन और समन्वय का माहौल देखने को मिला। प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र में और जिले में व्यापक स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं, जहां पर सड़क, पानी, बिजली, परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि देश विदेश के उद्योगपति प्रदेश में अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री खोल सके। जानकारी के अनुसार प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में, जहां जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे रेतीले जिले हैं, वहां पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई जगहों पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, ताकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को यहां सभी तरह की सुविधा और संसाधन उपलब्ध हो सके। इसी तरह से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के आदिवासी इलाकों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जैसे इलाकों में पर्यटन सर्किट का गठन करके वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस तरह से प्रदेश के हर क्षेत्र में सरकार ने पहले से ही देश और विदेश के उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की सुविधा और व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं, ताकि उद्योगपति देखते ही निवेश के लिए राजी हो जाए।

M/S Hari Prasad Sharma

M/S Hari Prasad Sharma
CONSTRUCTION
BUILD & RENOVATION

P.W.D Contractor

Mob.: 9983957498

राजस्थान के कोने-कोने से ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश पंजाब जैसे राज्यों से भी बड़ी संख्या में अपने लाडले का जन्मदिन मनाने गिरिराज जी धाम पहुंचे हजारों लोग।

जमीन से जुड़े नेता का जमीन से जुड़ा ऐतिहासिक जन्मदिन समारोह

जयपुर। राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया की लोकप्रियता जितनी राजस्थान में है, उससे कहीं ज्यादा उनकी लोकप्रियता दिल्ली, हरियाणा जैसे स्टेट में भी है। इसका ताजा उदाहरण सतीश पूनिया के जन्मदिन समारोह में उस समय देखने को मिला, जब गिरिराज जी धाम में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजस्थान के कोने-कोने से ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे। वैसे पूनिया की गिनती आज भाजपा के कुशल रणनीतिकारों में होती है। पूनिया ने पार्टी की ओर से दी गई प्रत्येक जिम्मेदारी को बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करके खुद को साबित भी किया। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ राजस्थान से निकलकर देश के अन्य राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है। शायद यही वजह रही कि गिरिराज धाम में आयोजित उनके जन्मदिन समारोह में हर जाति और बिरादरी के लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दिखाई। देश भर के बड़े-बड़े नेता, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद और भाजपा के संगठन से जुड़े नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे।

जानकार लोगों का कहना है कि बड़े राजनेताओं के जन्मदिन पर इस तरह का जलसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सतीश पूनिया के जन्मदिन के कार्यक्रम की तस्वीर और झांकियां सतीश पूनिया को जमीन से जुड़े नेता के रूप में बयां कर रही थी। वैसे भी सतीश पूनिया ठेठ किसान परिवार से ताल्लुक रखते

हैं और शुरू से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े रहने की वजह से इनका पूरा जीवन अनुशासित और जन सेवा के प्रति समर्पित रहा है। राजनीति में आने के बाद भी उनके व्यवहार, कार्यशैली और बोलचाल में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। उसी का परिणाम है कि उनके जन्मदिन समारोह को सेलिब्रेट करने के लिए अमीर-गरीब, हर जाति के लोग सैकड़ो किलोमीटर का सफर तय करके गिर्राज जी धाम पहुंचे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने अपने शुभचिंतकों से कहा कि परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों में किसी का जन्मदिन होता है, तो हम अक्सर कुछ ना कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट जरूर देते हैं। इसलिए उनके जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट देने के बदले उन पैसों का उनके शुभचिंतक किसी गरीब और आदिवासी बालिका का अकाउंट खुलवा दें, और बालिका के खाते का प्रिंट आउट निकालकर उनके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो वे सोचेंगे कि उनके शुभचिंतक ने उन्हें उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद दे दिया है। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर उन्होंने आदिवासी और गरीब बालिका के बैंक खाता खुलवाने का सिलसिला पूर्व में बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान शुरू किया था। उस समय उन्होंने मौके पर आठ बालिकाओं के अकाउंट्स प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाए थे। बाद में उनके आग्रह पर उनके प्रशंसकों ने अब तक पूरे प्रदेश भर में 50000 से ज्यादा आदिवासी और गरीब बालिकाओं के अकाउंट खुलवा दिए हैं, और बहुत जल्दी ही उनके प्रशंसक और शुभचिंतक इस आंकड़े को 1 लाख तक पहुंचा देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की

सतीश पूनिया ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की और कहा कि जब से मोदी ने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में ली है, तब से हर क्षेत्र में देश ने तेजी से प्रगति की है और देश में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह जनता से जुड़े छोटे-छोटे विषयों और छोटी-छोटी समस्याओं के बारे में बखूबी से जानकारी रखते हैं और फिर उन्हीं के अनुभव और आधार पर लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक सक्षम और शक्तिशाली नेता के हाथों में सुरक्षित है, जिनका भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान है। आज भारत को पूरे विश्व में सम्मान की निगाह से देखा जाता है और विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों और उनके आग्रह को गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि चाहे अयोध्या के राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 370 हटाने का मामला हो, ऐसे बड़े-बड़े निर्णय जो भारत की आजादी के बाद से ही भारत के लिए अभिशाप बने हुए थे, उन सब का निस्तारण करके नरेंद्र मोदी ने अब तक के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री में खुद को साबित किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी खूब तारीफ की

सतीश पूनिया ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी खूब तारीफ की। भजनलाल शर्मा की सादगी और उनके सरल व्यवहार के बारे में चर्चा करते हुए पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके इस जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर भी काफी गंभीर थे। उन्होंने फोन करके उनके जन्मदिन समारोह की तैयारी और व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा का इस तरह से उनके जन्मदिन के समारोह की व्यवस्थाओं के बारे में पूछना कोई साधारण बात नहीं है, यह मुख्यमंत्री शर्मा की एक अलग खूबी को बयां करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अब तक के कार्यकाल में हर क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। पानी, बिजली, सड़क, सौर ऊर्जा, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग हर क्षेत्र में पिछले 2 साल में जोरदार तरीके से विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही है, जो एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने का निर्णय लिया। इस तरह का निर्णय देश के अन्य राजनीतिक दलों में नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा ने एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित करके भी दिखाया है।

केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वृक्षारोपण को लेकर की तारीफ

अपने भाषण में सतीश पूनिया ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वृक्षारोपण को लेकर खूब प्रशंसा की और कहा कि वे विशेष रूप से चौहान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को नियमित रूप से रोजाना फॉलो करते हैं, और देखते हैं कि चौहान चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में हो, रोजाना जहां भी जाते हैं एक नया पेड़ लगाते हुए नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान की नई पेड़ लगाने की यह लगन देखकर वे खुद भी काफी चकित रहते हैं। पूनिया ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि राजस्थान जैसे स्टेट में वृक्षारोपण और भी जरूरी हो जाता है, इसलिए जन्मदिन समारोह, शादी समारोह, लग्न समारोह या अन्य खुशी के मौके पर आप किसी को एक पेड़ गिफ्ट के रूप में देंगे, तो यह एक बहुत अच्छी पहल होगी। क्योंकि पेड़ जब बड़ा हो जाता है, तो वह सिर्फ छाया नहीं बल्कि फल भी देता है और कई सालों तक आपकी यादों को ताज भी रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मां के नाम एक पेड़ अभियान के तहत पूरे देश में लोगों ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाए हैं, यह एक बहुत अच्छी शानदार शुरुआत देश में हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी बड़ी संख्या में नए पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने अपने शुभचिंतकों से कहा कि उनके जन्मदिन पर भी अगर आप एक पेड़ लगाओगे, तो वह उनके लिए उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा।

जन्मदिन समारोह के कौन-कौन से नेता बने साक्षी

वैसे तो सतीश पूनिया को देश भर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने फोन से जन्मदिन की बधाई दी, प्रेषित की और गिरिराज जी धाम क्षेत्र में आयोजित उनके जन्मदिन समारोह में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों से कई नेता यहां बधाई देने के लिए पहुंचे। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह, विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर, विधायक राजेंद्र भादू, विधायक रमेश खींची, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षी, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, सुखराम कोली, दिल्ली विधानसभा की सदस्य नीलम पहलवान, गोवर्धन विधायक मेघ श्याम सिंह, ठाकुर माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद और कई अन्य विशिष्ट जन और भाजपा के संगठन से जुड़े छोटे-बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, बीकानेर जैसे दूर दराज के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां सतीश पूनिया को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे।

पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह को भी किया याद

सतीश पूनिया ने अपने भाषण में पूर्व मंत्री दिवंगत डॉ दिगंबर सिंह को भी याद किया और कहा कि आज उनके क्षेत्र में ही मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम हो रहा है। उनकी कमी उन्हें काफी खल रही है, लेकिन उनके बेटे शैलेश दिगंबर अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की ओर तेजी से कम कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। सतीश पूनिया ने कहा कि डॉक्टर दिगंबर सिंह से उनके राजनीतिक तालुकात ही नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत तालुकात थे और कई सालों तक उन्होंने साथ-साथ काम किया, इसलिए उनके निधन से भाजपा को भी काफी क्षति पहुंची है, जिसकी पूर्ति होना असंभव है।

सतीश पूनिया ने कहा कि 'मैं राजनीति के लिए जन्मदिन नहीं मनाता '... सतीश पूनिया ने अपने भाषण में कहा कि उनके इतने लंबे पोलिटिकल कैरियर में कभी भी अपने जन्मदिन समारोह को राजनीति का जरिया नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि वह कभी भी राजनीति करने के लिए जन्मदिन नहीं मनाते। सतीश पूनिया ने कहा कि जब वह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, तब यहां गिरिराज जी के दर्शन करने आए थे, उस समय काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से गिरिराज जी की प्रतिमा को ठीक तरह से देख नहीं पाए थे। उस दिन उन्होंने यह संकल्प लिया था कि अगली बार आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से गिरिराज जी की प्रतिमा का दर्शन करेंगे, वह आशीर्वाद लेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बार अपना जन्मदिन अपने परिजनों और शुभचिंतकों के साथ गिरिराज जी के चरणों में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन पर सैकड़ो किलोमीटर का सफर तय करके शुभचिंतक यहां आए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज के इस व्यस्त जीवन में किसी के पास भी समय नहीं है, लेकिन यहां तो मैंने देखा पूरे दिन यहां बैठकर मेरे प्रशंसकों ने मुझे आशीर्वाद दिया। यह आत्मीय भाव मुझे हमेशा याद रहेगा।

जातिवाद की राजनीति से शुरू से ही दूर रहे हैं सतीश पूनिया

सतीश पूनिया छात्र जीवन से ही जातिगत राजनीति से दूर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में बड़े पदों पर कार्य करने के दौरान भी जातिवाद की राजनीति को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया, इसीलिए हर जाति और बिरादरी के छात्रों में लोकप्रिय रहे। संघ भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता, संघ में हर जाति और बिरादरी के लोग शामिल हैं। संघ से भी शुरू से ही सतीश पूनिया जुड़े हुए हैं, इसलिए जातिवाद की राजनीति में पुनिया कभी विश्वास नहीं रखते। जब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने जातिवाद की राजनीति को हमेशा बैक फुट पर रखा और ऊर्जावान और टैलेंटेड पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। वैसे सतीश पूनिया जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जाट समाज में भी इनका अच्छा प्रभाव और वर्चस्व है। जाट समाज के छोटे बड़े सभी संगठन इनका काफी आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन जातिगत राजनीति को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देते। इसीलिए इन्हें जमीन से जुड़ा किसान नेता माना जाता है।

सतीश पूनिया चाहते तो 2008 में ही विधायक बन जाते अपने टिकट की कुर्बानी देकर चर्चित भी रह चुके हैं

जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पूनिया को विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया था, लेकिन जब सतीश पूनिया को यह पता चला कि संघ समर्पित एक अन्य नेता फूलचंद भी इस क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने से बड़े उम्र के संघ समर्पित फूलचंद के लिए टिकट की कुर्बानी दे दी और सतीश पूनिया ने जानबूझकर खुद का टिकट कटवाया और फूलचंद को टिकट दिलवाया। उस समय सतीश पूनिया कि यह टिकट की कुर्बानी पूरे देश में चर्चा का विषय भी बनी थी, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में यह पहला मामला था, जब किसी ने आगे बढ़कर अपना टिकट कटवाया और किसी दूसरे नेता को टिकट दिलवाया। सतीश पूनिया ने टिकट ही नहीं दिलवाया, बल्कि भाजपा प्रत्याशी फूलचंद के लिए जोरदार चुनाव प्रचार किया, जिसकी वजह से वह चुनाव जीते भी। इसलिए जानकार लोगों का कहना है कि सतीश पूनिया उस समय आसानी से विराटनगर से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने से बड़े उम्र के नेता के प्रति सम्मान दिखाया।

भरतपुर जिले से ही हुई थी मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत

सतीश पूनिया ने अपने भाषण में जोड़ देकर कहा कि उनके पोलिटिकल कैरियर में भरतपुर का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि भरतपुर से ही उनकी पॉलिटिकल यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि 1989 में जब वह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे, तब उन्होंने सर्वप्रथम महान महापुरुष पृथ्वीराज चौहान के शहर अजमेर से पदयात्रा शुरू की थी। यह पदयात्रा महाराजा सूरजमल की धरती भरतपुर तक संपादित की गई थी। उनकी यह पहली और लंबी पदयात्रा थी, जो उनके पॉलिटिकल जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में कार्य करने के दौरान भी उनका भरतपुर आना जाना रहता था, इसलिए भरतपुर उनके लिए घर की तरह ही है।

प्रशासनिक व्यवस्था का स्वर्णिम अध्याय लिखने की काबिलियत रखते हैं वी श्रीनिवास

फूलों का नहीं, कांटों का ताज मिला है नए मुख्य सचिव को, अनेक खूबियों वाले इस सीनियर आईएएस अफसर ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अद्वितीय और अद्भुत बुद्धि कौशल और कार्यों की छोड़ रखी है छाप प्रदेश की 8 करोड़ की जनता और भजनलाल सरकार को श्रीनिवास से है काफी उम्मीद।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर के सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद आईएएस अफसर वी. श्रीनिवास कितने काबिल और टैलेंटेड अफसर हैं, यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि इन्हें राजस्थान और दिल्ली में बार-बार बुलाकर महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान केडर से जुड़े रहने के बावजूद भी इन्हें बार-बार दिल्ली बुलाया गया और फिर बार-बार ही राजस्थान में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। इनकी अद्भुत प्रशासकीय क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को साबित किया। यह अकेले भारत के ऐसे ऑफिसर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अध्यक्ष पद पर चुने गए। बाकायदा इनका निर्वाचन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग के आधार पर हुआ और उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक अधिकारी को अच्छे मतों के अंतर से हराया, जो भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए और भारत के लिए गौरव का विषय है। यह ऐसे अधिकारी हैं जो अपने डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था के कार्यों के लिए जितने देश और विदेश में लोकप्रिय और चर्चित रहे, तो उतने ही जमीन से जुड़ी सरकारी योजनाओं को ठीक तरह से संपादित करने के मामलों में भी अपनी अद्भुत छाप छोड़ी। इन्होंने गांव, खेती, उत्पादकता जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करके दिखाया। वर्षा आधारित कृषि में सर्वोच्च उत्पादन के लिए जो प्रयास और कार्य किया, उन्हें लोग आज भी नहीं भूले हैं। इसीलिए इन्हें नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की ओर से अवार्ड दिया गया। श्रीनिवास अपने नवाचारों, नए प्रयोग और विभागीय अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से अब तक की अपनी सरकारी नौकरी में जो कार्य किया है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने नौकरी नहीं की, बल्कि सर्विस को विजन की तरह जिया है और एक-एक पल का उपयोग लोगों की भलाई, प्रदेश और देश के विकास के लिए समर्पित भाव से किया। इसीलिए इन्हें बार-बार कभी दिल्ली तो कभी राजस्थान बदलाव की मंशा के साथ सरकारों ने काम करने का मौका दिया और इन्होंने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों को अपने कार्यों से प्रभावित किया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में श्रीनिवास को सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान मिला हुआ है, क्योंकि केंद्र और राजस्थान दोनों जगह पर भाजपा की सरकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, यह दोनों ही नेता देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान पर विशेष फोकस रखे हुए हैं। ऐसे में श्रीनिवास के राजस्थान में मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने की वजह के पीछे केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों का एक बहुत बड़ा विजन छिपा हुआ है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को उम्मीद है कि नए मुख्य सचिव श्रीनिवास राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वर्णिम अध्याय जरूर लिखेंगे, जो प्रदेश की जनता के लिए तो हितकर होगा ही, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में भी काफी सहायक होगा। हालांकि यह आसान कार्य नहीं है। कठिन और विपरीत परिस्थितियों में श्रीनिवास ने मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली है। श्रीनिवास यह भी जानते हैं कि यह फूलों का नहीं, बल्कि कांटों का ताज है, लेकिन उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता, अपने बुद्धि कौशल और लंबे प्रशासनिक अनुभव का भी अच्छी तरह से एहसास है। अब तक की उनकी सरकारी नौकरी में उन्होंने दिल्ली और राजस्थान में जितनी भी जिम्मेदारी संभाली, उन सब में इनका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। इसलिए अब एक बार फिर से श्रीनिवास ने दिल्ली से जयपुर की ओर अपना रुख किया, तो वह पूरे जोश और जज्बे के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए यहां आए हैं और प्रदेश के लोग इन्हें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।

बचपन में सरकारी स्कूल में वैदिक और संस्कृत धर्म ग्रंथो का भी अध्ययन किया, 22 साल की उम्र में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ

नए मुख्य सचिव श्रीनिवास का जन्म साधारण परिवार में हुआ। स्कूल की पढ़ाई भी ग्राम पंचायत के स्कूल में की। स्कूल की पढ़ाई में वैदिक और संस्कृत धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन किया। जब श्रीनिवास का जन्म तेलंगाना में हुआ था, उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। श्रीनिवास के पिता एंटोंमोलॉजिस्ट थे, जो नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। इसलिए श्रीनिवास बचपन में अपने माता-पिता के साथ मलेरिया प्रभावित गांव में ही रहे। इनकी माता उस समय वहां उन गिनी चुनी महिलाओं में थी, जो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। इसलिए बचपन से ही श्रीनिवास को घर पर माता-पिता से अच्छे संस्कार मिले। अनुशासन और सेवा भाव जैसे गुण बचपन से ही उनके दिल में समा गए थे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में बचपन बिताने से अभाव की जिंदगी जीते लोगों को नजदीकी से देखा था। शायद यही वजह है कि इन्होंने अब तक की अपनी सर्विस की नौकरी में जनता के लिए जारी की गई सरकारी योजनाओं का इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से क्रियान्वयन करवाया, ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। बचपन में वैदिक और संस्कृत धर्म ग्रंथ पढ़ने से श्रीनिवास ने अच्छे कर्म और अच्छे विचारों को अपने जीवन चरित्र में उतारा, जो अब तक उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बने हुए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद बचपन से ही श्रीनिवास पढ़ाई में काफी टैलेंटेड रहे। बाद में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1987 में केमिकल में बीटेक और 1989 में एमटेक किया तथा 22 साल की उम्र में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में इनका सिलेक्शन हुआ और राजस्थान कैडर दिया गया। लेकिन अपने शुरुआती प्रशासनिक सर्विस के दिनों में ही अपने अद्वितीय बुद्धि कौशल, नवाचार और अद्भुत प्रशासकीय नेतृत्व क्षमता से जो भी पद और जिम्मेदारी मिली, उसको शानदार ढंग से निभाया। जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में अपने कार्यों, अपनी वर्किंग स्टाइल, अपने नवाचारों तथा डिजिटल प्रशासनिक क्षमता के अद्वितीय कौशल से देश के श्रेष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की लिस्ट में टॉप पर नजर आने लगे।

राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी रहे, करीब 10 साल तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आंध्रप्रदेश की बैडमिंटन टीम के कैप्टन भी रहे

प्रदेश के नए मुख्य सचिव श्रीनिवास जितने पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि और टैलेंटेड थे, उतने ही खेलने में भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर हमेशा आगे रहे। बैडमिंटन में 1980 से 1989 तक करीब 10 साल तक हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आंध्र प्रदेश की बैडमिंटन टीम के कप्तान रहे और राष्ट्रीय स्तर पर अपने श्रेष्ठ खेल प्रदर्शन की छाप छोड़ी। अपनी यूनिवर्सिटी को कई मेडल दी, जितने पढ़ाई में चैंपियन रहे उतने ही खेल में भी चैंपियन रहे। 1984 में जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऑल इंडिया के नरंग कप जीता और 1989 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में उस्मानिया बैडमिंटन टीम की कप्तानी करके टीम को गोल्ड मेडल जिताया। बचपन से ही श्रीनिवास की कद काठी काफी अच्छी थी। खूबसूरत तो दिखते थे ही, इसके अलावा अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण होने से इनकी एक अलग ही पर्सनालिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जमाने से ही नजर आने लगी थी, जो आज तक बरकरार है। जितने शारीरिक रूप से मजबूत है, उतने ही मानसिक रूप से भी काफी मजबूत है। नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच के धनी तो है ही, इसके अलावा गरीब, मजदूर, किसान और जरूरतमंद लोगों के कल्याण और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या राजस्थान सरकार, जिस भी सरकार ने इन्हें जिस भी जनकल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को नौकरी समझ कर नहीं, बल्कि विजन के रूप में बखूबी से निभाया।

1989 से अब तक राजस्थान और केंद्र में कई विभागों में बड़ी जिम्मेदारी निभाई

श्रीनिवास का 1989 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। शुरुआती सर्विस के दिनों में 1989 से 2000 तक राजस्थान में अलग-अलग जगह पर नियुक्त रहे। राज्य के डिपार्टमेंट में उप सचिव, जोधपुर और पाली के जिला कलेक्टर रहे। इसके अलावा जल ग्रहण विकास एवं मुद्रा संरक्षण विभाग के निदेशक रहे तथा आईजीएनपी में अपर क्षेत्रीय विकास आयुक्त और उप प्रभारी अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त रहे। इसके बाद श्रीनिवास को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया। वर्ष 2003 से वर्ष 2006 तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान श्रीनिवास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन में कार्यकारिणी निदेशक सलाहकार के पद पर नियुक्त रहे। इसके बाद फिर 2007 से 2010 तक श्रीनिवास को राजस्थान में अलग-अलग जगह पर नियुक्त किया गया, जिसमें राज्य के योजना एवं वित्त विभाग बजट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव पद पर भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद श्रीनिवास को वापस दिल्ली बुला लिया गया, जहां 2010 से 2017 तक अलग-अलग जगह पर इन्हें काम करने का अवसर दिया गया। जिसमें भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, विदेश विभाग जैसे बड़े विभागों में संयुक्त सचिव पद पर कार्य करने का मौका दिया गया। इसके अलावा दिल्ली एम्स में उपनिदेशक प्रशासन के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यहां इस पद पर रहते हुए इन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लेकर क्रांतिकारी बदलाव किया, जो आज भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसके अलावा संस्कृति विभाग में संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय अभिलेखागार में महानिदेशक पद पर कार्य किया। 2017 में इन्हें वापस राजस्थान बुलाया गया और राजस्थान टैक्स बोर्ड और राजस्थान राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्हें दिया गया। इस तरह से श्रीनिवास की अब तक की सरकारी सर्विस पर निगाह डालें तो साफ दिखता है कि जितनी राजस्थान सरकार को इनकी जरूरत थी, उतनी ही जरूरत इनकी केंद्र सरकार को भी थी। इसलिए इन्हें कभी दिल्ली तो कभी राजस्थान कार्य करने का अवसर दिया गया। हालांकि देश के अन्य राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाते रहे हैं, राजस्थान से भी कई अधिकारी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में गए हुए हैं, लेकिन श्रीनिवास अकेले अधिकारी हैं जिन्हें बार-बार दिल्ली और राजस्थान कार्य करने के लिए बुलाया गया, जो यह दिखाता है कि उनकी वर्किंग शैली से केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों काफी प्रभावित हैं। इसलिए दोनों ही सरकारें उनके अनुभव का फायदा उठाने का प्रयास करती रहती हैं।

राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और दिल्ली में आवासीय आयुक्त की जिम्मेवारी भी मिली

श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त हो गए हैं। इसके अलावा इन्हें राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष भी बनाया गया है तथा दिल्ली में आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई है। इन सब में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी देने का सरकार का निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में खान विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह विभाग भ्रष्टाचार को लेकर भी कई सालों से प्रदेश में सुर्खियों में रहा है। अब जिस तरह से श्रीनिवास को प्रदेश के खान और खनिज सेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह निश्चित रूप से प्रदेश की इकोनॉमी को गति देने और मजबूत देने में काफी सहायक साबित होगी। खान सेक्टर में प्रदेश की भजनलाल सरकार डिजिटल सिस्टम को मजबूती से लागू करने का प्रयास कर रही है। श्रीनिवास, जो पहले से ही डिजिटल प्रशासनिक क्षमता के लिए पूरे देश में माने जाते हैं, अपने इस अनुभव और नए तरीकों प्रयोग को खान सेक्टर में भी लागू करके खान विभाग में कथित भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी तरफ खान विभाग से प्रदेश की तिजोरी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इसके लिए भी श्रीनिवास की ओर से नए प्रयोग और नए तरीकों के लागू होने की संभावना है। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने और बंद पड़ी खान को फिर से शुरू करने के प्रयास भी श्रीनिवास की ओर से किए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं प्रदेश के खान सेक्टर को ईमानदारी से और ठीक तरह से प्रबंध किया जाए, तो प्रदेश की तिजोरी में काफी पैसा आ सकता है, क्योंकि अवैध खनन की वजह से यहां हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल सरकार को उठाना पड़ रहा है। सरकार चाहते हुए भी अवैध खनन को नहीं रोक पा रही, हालांकि यह भी सच है कि खान विभाग प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की आपस की सेटिंग की वजह से प्रदेश में अवैध खनन अब से नहीं, बल्कि कई सालों से संचालित होता आ रहा है। लेकिन अब श्रीनिवास को राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी देने के बाद कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार आएगा, जो कहीं ना कहीं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ प्रदेश की तिजोरी में भी खान विभाग से अच्छा पैसा मिलेगा।

पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत नरसिम्हा राव के रिश्तेदार है श्रीनिवास

पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत जसवंत सिंह के निजी सचिव भी रहे

प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीनिवास पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत नरसिम्हा राव के रिश्तेदार भी है। श्रीनिवास की पत्नी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की रिश्ते में दोहिती लगती हैं। इसके अलावा पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार के समय पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत जसवंत सिंह के निजी सचिव भी श्रीनिवास रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना तैयार की थी, इसकी पटकथा लिखने में श्रीनिवास की बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान की राजनीति और राजस्थान सरकार के कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही नजर जमाए हुए हैं। राजस्थान में पिछले 30 सालों से हर 5 साल में सरकार बदलने का सिलसिला बना हुआ है, इसलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं कि राजस्थान में यह सिलसिला टूटे नहीं और प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति भरोसा बना रहे। इसलिए प्रदेश की भजनलाल सरकार को केंद्र सरकार हर तरह से सपोर्ट कर रही है। केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच अच्छा तालमेल बना हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में कई बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रोजेक्ट के काम जारी है। इसलिए इन सभी कार्यों का निर्धारित समय पर संपादन हो और सभी कार्य ठीक तरह से समुचित तरीके से संपन्न हो, इसलिए प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में श्रीनिवास को राजस्थान भेजा गया है। तो चर्चा यह भी है कि भजनलाल सरकार और सुधांशु के बीच कहीं ना कहीं तालमेल और समन्वय में कमी आ गई थी, जिसकी वजह से प्रदेश में मुख्य सचिव को बदलना जरूरी हो गया था, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों में कोई अड़चन नहीं आए और प्रदेश तथा केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न तरह की जनकल्याणकारी योजनाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो। इसलिए डिजिटल प्रशासनिक क्षमता के अद्भुत धनी श्रीनिवास को मुख्य सचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई।

सितंबर 2026 में रिटायर होंगे श्रीनिवास

सरकार चाहे तो 6-6 महीने के दो एक्सटेंशन दे सकती है

नए मुख्य सचिव श्रीनिवास सितंबर 2026 को सेवानिवृत्ति होंगे, इसलिए मुख्य सचिव के रूप में अपनी नौकरी की अंतिम पारी को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए उनके पास सिर्फ 10 महीने का समय मिला है। हालांकि यह समय कम है, लेकिन फिर भी इन 10 महीने में भी श्रीनिवास प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में काफी कुछ क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कई विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के दौरान कई क्रांतिकारी निर्णय लिए, कई नवाचार किये, जिनका फायदा लोगों को अब तक मिल रहा है। इसलिए भले ही 10 महीना हो, लेकिन श्रीनिवास एक ऐसे अफसर हैं जो इन 10 महीनों में भी काफी कुछ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास काबिलियत है और देश-विदेश में नौकरी करने का लंबा अनुभव है। विदेश के कई ब्यूरो **कैरेटस** के संपर्क में रहे हैं, कई देशों की प्रशासकीय व्यवस्था का भी इन्हें अच्छा नॉलेज है। इसलिए जानकार लोगों का कहना है कि श्रीनिवास इन 10 महीना में भी राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक नया परिवर्तन और क्रांतिकारी युग की शुरुआत कर सकते हैं। इसी मकसद से उन्हें दिल्ली से जयपुर लाया गया है। हालांकि राज्य सरकार अगर उनके कार्यों से प्रभावित और खुश होगी, तो निश्चित रूप से इन्हें 6-6 महीने के दो एक्सटेंशन भी मिल सकते हैं। इससे पहले भी प्रदेश के कई मुख्य सचिव को उनके रिटायरमेंट होने के बाद सरकारों ने उनका कार्यकाल बढ़ाया, इसलिए कहा जा रहा है कि श्रीनिवास का कार्यकाल भी सरकार बढ़ा सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह कभी नहीं चाहेंगे इस श्रीनिवास जैसे अफसर के अनुभव का फायदा सरकार और जनता को नहीं मिले। इसलिए यह प्रबल संभावना है कि जब 2026 के सितंबर में श्रीनिवास रिटायरमेंट होंगे, तो सरकार उनका पहला 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा सकती है और फिर यह 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद आगे और 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा सकती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव श्रीनिवास की यह नई जोड़ी प्रदेश में रचेगी नया इतिहास!

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्मठ और ईमानदार तथा कार्य के प्रति समर्पित राजनेता माने जाते हैं, इसलिए पिछले 2 साल के अपने कार्यकाल में अपने कार्यों से पूरे देश में उन्होंने खुद को श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में साबित किया है। इधर प्रदेश के नए मुख्य सचिव श्रीनिवास भी ईमानदार, मेहनती और डिजिटल प्रशासनिक क्षमता के अद्भुत धनी हैं। इसके अलावा तकनीकी का भी बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। इनके पास देश और विदेश में प्रशासनिक कार्य करने का काफी लंबा अनुभव है। श्रीनिवास का बचपन भी गांव में बीता है, स्कूल की पढ़ाई गांव में की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लंबा समय गांव में बिताया है, इसलिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों में काफी समानता है। दोनों ही गांव, गरीब, किसान, मजदूर और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखने के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में नई-नई योजना और नए-नए विकास प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुख्य सचिव श्रीनिवास प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा नवाचार, तकनीकी और डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रहे हैं। इसलिए राजस्थान में अब केंद्र और राजस्थान सरकार की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं के और भी अच्छे ढंग से संचालित होने की बातें कहीं जा रही है, क्योंकि और मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की यह नई जोड़ी विकसित राजस्थान के विजन के साथ नए जोश और नए उत्साह से कार्य करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी, जो प्रदेश की जनता और प्रदेश की तरक्की का नया इतिहास भी लिख सकती है।

अच्छे लेखक और शोधकर्ता होने के अलावा श्रेष्ठ लेक्चरर्स भी रहे

नए मुख्य सचिव श्रीनिवास ने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े मंच शेयर किये। इन अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर दुनिया भर के विशेषज्ञों की ओर से अलग-अलग समय में अलग-अलग विषयों पर संगोष्ठी, विचार गोष्ठी जैसे आयोजन में श्रीनिवास ने सारगर्भित और तथ्यात्मक तरीके से कई विषयों पर अपने विचार रखे, जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया गया। इन महत्वपूर्ण मंचों पर दुनिया भर के विशेषज्ञ लोगों की ओर से प्रस्तुत किए गए विचारों का संकलन करने में भी श्रीनिवास कभी पीछे नहीं रहे। श्रीनिवास हमेशा नए प्रयोग और नए आइडिया हर क्षेत्र में लागू करने की ओर देखते रहते हैं। इसके लिए दुनिया भर का माहौल और दुनिया भर के लोगों के विचार जानना भी जरूरी रहता है। इसीलिए श्रीनिवास ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस जिस विषय पर मंच शेयर किया, उनका उन्होंने निचोड़ निकालने का प्रयास भी किया। इसके लिए उन्होंने अनेक शोध पत्र लिखें। करीब 250 शोध पत्र अब तक श्रीनिवास लिख चुके हैं। इसके अलावा 175 से ज्यादा बार लेक्चरर्स अनेक विषयों पर अलग-अलग जगह पर दे चुके हैं। अपनी सर्विस के दौरान श्रीनिवास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी पोस्टेड रह चुके हैं। यहां पोस्टिंग के दौरान भी उन्होंने जो अनुभव हासिल किये, उन पर शोध पत्र लिखें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 25 वर्ष के विश्लेषण को लेकर भी श्रीनिवास ने बहुत ही तथ्यात्मक और सारगर्भित तरीके से शोध लिखें, जिन्हें दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। श्रीनिवास ने जी-20 की भारतीय अध्यक्षता पर भी शोध पत्र लिखा, जो अपने आप में एक अनूठा दस्तावेज है। श्रीनिवास ने द मैच टू न्यू इंडिया जैसी किताब भी लिखी है, जो काफी सुर्खियों में रही। जानकारों का कहना है कि श्रीनिवास की प्रशासकीय अद्भुत लीडरशिप क्षमता, डिजिटल प्रशासनिक क्षमता और अपनी तकनीकी निपुणता के दम पर इन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की ब्यूरोक्रेसी में भी लोकप्रियता हासिल की।

दिल्ली एम्स में श्रीनिवास की ओर से किए गए क्रांतिकारी बदलाव की चर्चा पूरे देश में

प्रदेश के मुख्य नए सचिव श्रीनिवास जब दिल्ली एम्स में डिप्टी डायरेक्टर पद पर नियुक्त थे, तब उन्होंने वहां डिजिटल एम्स प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। जिसमें ई-हॉस्पिटैलिटी के शुरू होने से मरीजों की जो पहले लंबी लाइन लगा करती थी, वह लाइन लगना बंद हो गई। मरीजों को पहले काफी परेशानी हुआ करती थी, उस परेशानी से मरीजों को मुक्ति मिली। श्रीनिवास की ओर से लागू की गई यह नई व्यवस्था पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और इस नई व्यवस्था को देश के कई राज्यों ने लागू किया। श्रीनिवास के ये नए नवाचार आज भी दिल्ली एम्स में इलाज के लिए आने वाले लोगों में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी अपनी नियुक्ति के दौरान श्रीनिवास ने डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी तथा पारदर्शक ढंग से कार्य हो सके। श्रीनिवास के बारे में कहा जाता है कि प्रशासकीय कार्य में ज्यादा से ज्यादा आधुनिकरण हो और ज्यादा से ज्यादा नवाचार, नए प्रयोग किए जाएं तथा तकनीकी का बखूबी से इस्तेमाल किया जाए, तो इससे एक नहीं, कई तरह के फायदे होते हैं। जिसमें समय और धन की बचत तो होती ही है, इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लगता है। इसलिए अब जिस तरह से श्रीनिवास ने यहां मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली है, चर्चा है कि अब राजस्थान के प्रशासनिक हल्के में आधुनिकरण और डिजिटल सिस्टम की भरमार देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एक तरफ लोगों के काम जल्दी संपादित होंगे, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार जैसी कोई शिकायत भी सामने नहीं आएगी।

कांग्रेस में जूली की ऊंची उड़ान, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में खुद को साबित किया

विधानसभा में हर विषय पर सटीक और तथ्यात्मक भाषण देकर पूरे सदन को किया प्रभावित, गांधी परिवार और दिल्ली में बैठे पार्टी के सभी बड़े नेता भी इनके परफॉर्मेंस से हैं काफी प्रभावित, प्रमोद जैन भाया की जीत में भी निभाई बड़ी भूमिका

जयपुर। प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में टीकाराम जूली ने खुद को साबित किया है। जूली हर विषय पर पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में आते हैं और फिर बहुत ही सटीक और तथ्यात्मक तरीके से अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं। उनके भाषण की सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि वह कड़वी से कड़वी बात में भी इतनी मिठास मिला देते हैं कि सत्ता पक्ष को उनकी बातें चुभती तो हैं, लेकिन इतना दर्द भी नहीं देती कि सत्ता पक्ष सदन में हंगामा करने को मजबूर हो जाए। जूली की कोशिश भी यही रहती है कि विधानसभा ठीक तरह से संपादित हो, ताकि प्रदेश के लोगों को सदन की कार्रवाई से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसलिए उनकी आलोचना करने का तरीका बेहद ही शानदार रहता है, जो अंदर ही अंदर सत्ता पक्ष के लोगों के दिलों को बेचैन करने के साथ-साथ उनकी बातों पर कार्रवाई करने के लिए सत्ता पक्ष को मजबूर भी करता है। इसीलिए जूली के भाषण को सुनना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अच्छा भी लगता है और उन्हें सुनने के लिए सदन के सदस्यों में उत्सुकता भी बनी रहती है। वैसे जूली राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में ऐसे पहले दलित नेता हैं, जिन्हें विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनने का सौभाग्य मिला। इसमें कोई संदेह नहीं, प्रदेश की भजनलाल सरकार में अब तक जितनी भी विधानसभा की बैठक आयोजित हुई है, उनमें जूली ने अपनी भूमिका को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। सत्ता पक्ष को हर मुद्दे पर उन्होंने सदन में अपने सटीक और तथात्मक भाषण के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा पार्टी के सभी विधायकों को एकजुट बनाए रखने में भी उनकी भूमिका काफी अच्छी कहीं जा सकती है। वजह यह है कि जूली कांग्रेस के एक ऐसे नेता माने जाते हैं, जो अपने सीधे सरल और मधुर व्यवहार से पार्टी की गुटबाजी से खुद को अलग रखते हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं का सम्मान करना और पार्टी के नौजवान युवा नेताओं को गले से लगाकर उनका ठीक तरह से मार्गदर्शन करना उनके स्वभाव में है। उनकी यही खासियत उन्हें राजस्थान कांग्रेस में नई बुलंदियों पर पहुंचा रही है। सिर्फ 24 साल की आयु में अलवर जिला प्रमुख पद पर विराजमान होने वाले जूली की नेतृत्व क्षमता और उनकी राजनीतिक कुशलता प्रतिपक्ष के पद पर विराजमान होने के बाद खुलकर देखने को मिली है, जिसे देखकर कांग्रेसी आलाकमान भी इस दलित नेता से काफी प्रभावित है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा है कि प्रतिपक्ष नेता पद की भूमिका का शानदार ढंग से निर्वाहन करके जूली राजस्थान कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में शामिल हो गए हैं, इसलिए आने वाले दिनों में इन्हें और भी बड़ी जिम्मेवारी मिलना सुनिश्चित भी है।

अंता में प्रमोद जैन भाया की जीत में जूली का बहुत बड़ा योगदान रहा

अंता विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत में टीकाराम जूली का योगदान बहुत बड़ा रहा है। अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया से जुड़े लोगों का कहना है कि उपचुनाव में जूली के चुनाव प्रचार और उनकी मेहनत को देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे जूली यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि यहां चुनाव प्रचार के लिए कई दिनों तक जूली ने यहां डेरा डाले रखा और बाकायदा रोजाना अपना कार्यक्रम निर्धारित करके सुबह से लेकर देर रात तक क्षेत्र में लोगों के बीच पार्टी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करते नजर आए। घर-घर जाकर लोगों से मिलना और उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए राजी करना, यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां रोड शो के माध्यम से भाजपा के पक्ष में जोरदार माहौल बनाने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे। इसके अलावा भजनलाल सरकार के कई मंत्री और विधायक भी यहां पर डेरा डाले हुए थे। दलित वोटो को देखते हुए भाजपा ने उपमुख्यमंत्री और दलित नेता डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को यहां चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी दी हुई थी, लेकिन इन सबके बीच जूली ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रमोद जैन भाया की ओर से यहां अपने कार्यकाल में किए गए कामों और पिछली गहलोत सरकार में लागू की गई उल्लेखनीय जनकल्याणकारी योजनाओं इत्यादि का जिक्र करके लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास मजबूत करने का अच्छा प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। बड़ी बात यह रही कि अंता विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी इस क्षेत्र में दलित समुदाय के मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए जूली को बड़ी जिम्मेदारी दी हुई थी, जिसको निभाने में जूली पूरी तरह से सफल हुए। जूली साधारण से दलित परिवार से निकले हुए जमीन से जुड़े नेता हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को ठीक तरह से समझते हैं। इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान भी जूली अपने प्रभावी भाषण से ग्रामीण इलाकों के हर जाति और बिरादरी के लोगों को भावनात्मक रूप से कांग्रेस से जोड़े रखने में सफल रहे। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में जूली ने जो परफॉर्मेंस किया, उसका अच्छा मैसेज प्रदेश की जनता में गया है, इसलिए जूली की ओर से कही गई बातों को ग्रामीणों ने एक्सेप्ट भी किया। उसी का नतीजा रहा की अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने ही नहीं, बल्कि जूली ने जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, वहां के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को ज्यादा वोट डाले, जिसकी वजह से प्रमोद जैन भाया को यहां सफलता मिली। इस बात को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि जूली ने यहां पर काफी मेहनत की और उन्होंने जूली को उनकी मेहनत के लिए शाबाशी भी दी, अन्यथा इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत को आसान माना जा रहा था, क्योंकि वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे। वसुंधरा राजे दो बार की मुख्यमंत्री और पांच बार झालावाड़ से सांसद रह चुकी है। इसी तरह से दुष्यंत सिंह भी पांचवीं बार झालावाड़ से सांसद चुने गए। अंता विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के तहत ही आता है, इसलिए हर कोई यह कह रहा था इस बार भी भाजपा को ही यहां जीत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहां अंदरूनी रूप से जमीनी तौर पर पार्टी का प्रचार प्रचार करने का निर्णय लिया। इसमें टीकाराम जूली, अशोक चांदना जैसे नेताओं को यहां बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसी का नतीजा रहा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में सफलता मिली।

प्रतिपक्ष के नेता पद पर जूली का चयन किए जाने के पीछे क्या था बड़ा राज ?.....

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को यहां विपक्ष में बैठने का मौका मिला, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता के चयन का कार्य कांग्रेस के दिल्ली दरबार के लिए बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि कांग्रेस का दिल्ली दरबार भी राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच आपस में चल रहे टकराव की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए यहां पर कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं ने एक ऐसे नेता को प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना ज्यादा जरूरी समझा, जिसके नाम को लेकर कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता को आपत्ति ना हो, साथ ही वह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को संभालने की हैसियत भी रखता हो, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता पद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे कोई भी पार्टी हो, यह बड़ा पद उस नेता को देती है, जो सत्ता पक्ष को अपने सटीक भाषण और अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से सदन में झुकने को मजबूर कर दे। ऐसे में काफी सोच विचार करके कांग्रेस हाई कमान ने चुने हुए विधायकों में टीकाराम जूली को इस पद के काबिल समझा। हालांकि चर्चा यह भी हुई थी कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रतिपक्ष का पद भी दे दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बड़े पद होते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की वजह से डोटासरा को प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी नहीं दी गई। हालांकि पूर्व में डोटासरा प्रतिपक्ष नेता पद की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा भी चुके थे, लेकिन डोटासरा को दोनों में से एक ही पद पर रखा जाना निश्चित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर डोटासरा को बनाए रखना कांग्रेस पार्टी ने जरूरी समझा और प्रतिपक्ष बनाए रखना कांग्रेस पार्टी ने जरूरी समझा और प्रतिपक्ष नेता पद की जिम्मेदारी जूली को दिया जाना तय किया गया। जूली को प्रतिपक्ष नेता पद की जिम्मेदारी देने के पीछे के कुछ बड़े कारण रहे, जिनमें सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि जूली के नाम पर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने किसी भी तरह की कोई आपत्ती नहीं जताई, क्योंकि जूली काफी मिलनसार, सीधे सरल और काफी कुशल और युवा राजनेता के तौर पर पार्टी में माने जाते हैं। टीकाराम जूली तीसरी बार अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। जूली के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या अन्य किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। इस बात को कांग्रेस के दिल्ली में बैठे-बैठे नेता भी जानते थे कि जूली के नाम पर राजस्थान कांग्रेस के सभी बड़े नेता सहमत भी नहीं होंगे, तो नाराज भी नहीं होंगे। और वही हुआ, जब जूली को प्रतिपक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई, तो किसी भी नेता ने आपत्ति और नाराजगी जाहिर नहीं की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने जूली को प्रतिपक्ष का नेता पद देकर दलित कार्ड का भी खेल किया। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब किसी दलित नेता को विधानसभा में प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई हो। यह अपने आप में प्रदेश के दलित समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी के भरोसे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम था। इसके अलावा जूली वर्ष 2008 और 2018 की गहलोत सरकार में गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे और मंत्री के रूप में भी जूली ने खुद को श्रेष्ठ साबित करके दिखाया था। यही वजह रही की 2023 के विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार के अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन टीकाराम जूली ने बड़े मतों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से हराया। बाद में टीकाराम जूली के प्रतिपक्ष का पद संभालने के बाद उन्होंने राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो भूमिका निभाई, उस भूमिका को देखकर राजस्थान कांग्रेस के बड़े लीडर ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता भी जूली के परफॉर्मेंस से काफी खुश और प्रभावित हैं। इस तरह से अब कांग्रेस हाई कमान को भी अपने निर्णय पर गर्व हो रहा है कि उन्होंने जूली को प्रतिपक्ष का बड़ा पद देकर कोई गलत निर्णय नहीं लिया।

जिला प्रमुख से लेकर प्रतिपक्ष पद तक ऐतिहासिक पॉलीटिकल यात्रा रही है टीकाराम जूली की

जूली का जन्म बहरोड क्षेत्र के कडू वास गांव में एक साधारण से दलित परिवार में हुआ था। हालांकि इनके पिता गांव के सरपंच भी रहे और सरपंच पद पर रहते हुए राजनीति में पांव जमाने का प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अपने पिता के ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में खुशहाली लाने के सपनों को साकार करने की दिशा में टीकाराम जूली ने अब तक राजनेता के रूप में बहुत ही शानदार काम करके दिखाए। जूली के पिता भले ही राजनीति में सक्सेस नहीं हुए हो, लेकिन अपने पिता के सपनों और उनकी उम्मीदों को जूली पंख लगाए हुए हैं और अब तक की पॉलिटिकल यात्रा में उन्होंने एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के दिलों पर राज किया, तो दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस में भी बुलंदियों को छूने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2004 में अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में उन्होंने जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव जीत और फिर अलवर के जिला प्रमुख भी बने। बाद में 2008 में कांग्रेस पार्टी की ओर से अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मिला, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जगदीश प्रसाद को 8525 वोटो से हराया और पहली बार राजस्थान विधानसभा की चौखट को छुआ और पहली बार में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी किया। गहलोत ने इन्हें श्रम विभाग स्वतंत्र प्रभार के रूप में जिम्मेदारी दी, जिसमें कारखाना एवं ब्वॉयलर्स, सहकारिता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे विभाग इन्हें दिए गए। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें फिर से अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन इस चुनाव में इनको पराजय मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम जाटव ने इन्हें करीब 7000 वोटो से हराया। लेकिन अगले ही चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव में टीकाराम जूली ने अपनी पिछली पराजय का बदला लेते हुए भाजपा प्रत्याशी रामकिशन मास्टर को करीब 26477 वोटो से हरा दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली, अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बने और गहलोत ने इन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी थी। इसके बाद वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां गहलोत सरकार के अधिकांश मंत्री चुनाव हारे, वही टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 108584 वोट हासिल करके चुनाव जीते। इस चुनाव में इन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी भाजपा के जयराम जाटव को हराया। बड़ी बात यह है कि गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल और गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री पद पर रहते हुए जूली ने बहुत ही श्रेष्ठ काम करके अशोक गहलोत को तो अपनी राजनीतिक कुशलता और अनुभव से प्रभावित किया ही, इसके अलावा प्रदेश की जनता के कल्याण और विकास के लिए अपने विभागों के माध्यम से इन्होंने हर तरह से नई योजनाएं और नए नवाचार लागू करके लोगों को राहत पहुंचाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री के तौर पर इन्होंने समाज में निम्न स्तर के लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, निम्न स्तर के परिवारों के बच्चों को शिक्षित टैलेंटेड बनाने के लिए इन्होंने मंत्री के तौर पर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। दलित परिवारों और वंचित परिवारों की बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बालिकाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लागू की। इसी तरह से विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांगजन, बुजुर्ग इत्यादि सभी जरूरतमंद लोगों के जीवन को सुखद बनाने के लिए जूली ने मंत्री के तौर पर भलाई के खूब निर्णय लिए, जिसका जरूरतमंद लोगों को खूब फायदा भी मिला। इसलिए 2023 के चुनाव में भले ही गहलोत के अन्य सारे मंत्री हार गए हो, लेकिन जूली अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीते और अब प्रतिपक्ष के नेता पद की जिम्मेदारी निभाने के दौरान भी टीकाराम जूली हर जाति और बिरादरी के लोगों की राजस्थान विधानसभा में आवाज बने हुए हैं, हर मुद्दे को दमदार तरीके से उठा रहे हैं और हर विषय पर प्रखर भाषण देकर सत्ता पक्ष की जोरदार घेराबंदी करके उनके लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

सदन के गतिरोध को दूर करने में हमेशा आगे रहे

जानकार लोगों का कहना है कि टीकाराम जूली ग्रामीण इलाके से वास्ता रखते हैं। वह यह भी जानते हैं कि ग्रामीण इलाके की जनता जिसमें किसान मजदूर अब भी कितनी मुसीबत के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए राजस्थान विधानसभा एक ऐसा मंच है, जहां पर प्रदेश की जनता के कल्याण और विकास के लिए योजनाएं बनती हैं। जूली यह भी जानते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक एक सेकंड पर कितना पैसा खर्च होता है, इसलिए जूली की हमेशा यह कोशिश रहती है कि विधानसभा के संचालन के लिए जो लाखों रुपए रोजाना खर्च होते हैं, उनका सदुपयोग हो। और यह सदुपयोग तभी हो सकता है, जब विधानसभा की कार्रवाई ठीक तरह से संपादित हो। इसलिए जूली की हमेशा यह कोशिश रहती है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध तरीके से चलती रहे, सरकार के मंत्री सदन के सदस्यों के सवालों का जवाब दें, विपक्ष का सदस्य हो या फिर सत्ता पक्ष का कोई सदस्य किसी विषय पर कोई डाउट रखना हो, तो उस डाउट को सत्ता पक्ष दूर करें। टीकाराम जूली उन नेताओं में नहीं है, जो सदन में सिर्फ हंगामा मचाकर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के बारे में सोच रखते हो, लेकिन फिर भी राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्रों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपस में कई बार टकराव के हालात बने, जिसकी वजह से कई दिनों तक सदन की कार्रवाई ठीक तरह से संपादित नहीं हो पाई। कई दिनों तक गतिरोध की स्थिति बनी रही, चाहे जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के बीच आपस में बहस के मामले को लेकर तो कई दिनों तक सदन में गतिरोध की स्थिति बनी रही। डोटासरा बुरी तरह से भड़क गए थे और उन्होंने राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई से खुद को पूरी तरह से अलग भी कर लिया था। इस बीच प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी टीकाराम जूली के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि प्रदेश की जनता ने उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की दी है, इसलिए इस गतिरोध को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से भरपूर प्रयास भी किया। जूली यह भी जानते थे कि इस गतिरोध से पूरा बेनिफिट सत्ता पक्ष को हो रहा है, सत्ता पक्ष सदन में अपने हिसाब से कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, वहां पर सत्ता पक्ष को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए जूली इस गतिरोध को दूर करने के लिए सतत प्रयास करते रहे। बाद में उन्होंने अशोक गहलोत को साथ लेकर इस गतिरोध को दूर भी किया, ताकि सदन में सत्ता पक्ष के सामने बैठकर उनसे सवाल-जवाब किया जा सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को जूली की ओर से गतिरोध को समाप्त करने की पहल करना अच्छा भी नहीं लगा था। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता तभी जुबान से इसे ठीक नहीं मान रहे थे, लेकिन जूली ने प्रदेश की जनता की आवाज को सदन में उठाने के लिए इस गतिरोध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना जरूरी समझा और इसी परिपेक्ष में उन्होंने गतिरोध को दूर करने के लिए अशोक गहलोत जैसे नेताओं को साथ लिया और फिर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और सत्ता पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करके गतिरोध को दूर करवाया।

हर रोज जूली के नेतृत्व में विपक्ष के सदस्यों का विधानसभा तक पैदल मार्च आकर्षण का केंद्र रहा

राजस्थान विधानसभा के इतिहास में इस बार यह पहली बार देखने को मिला, जब विधानसभा सत्र के दौरान रोजाना प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में विपक्ष के सदस्यों ने रोजाना नए-नए मुद्दों को लेकर विधायक आवास से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। जी हां, चाहे प्रतिपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी, अब तक बहुत कम बार ही ऐसे देखा गया है, जब विपक्ष के सदस्य विधानसभा में पैदल मार्च करते हुए अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक पहुंचे हो। इस तरह के मुश्किल से एक या दो दिन तक विधानसभा कार्रवाई के विपक्ष की ओर से किए जाते रहे हैं, या फिर सदन की कार्रवाई में विपक्ष के सदस्यों को सदन से निलंबित कर देने पर विपक्ष के नेता की अगुवाई में इस तरह के प्रदर्शन विधानसभा परिसर में करते हुए देखे गए। लेकिन टीकाराम जूली के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार देखा गया, जब सदन की करवाई जितने दिन भी चली, उतने दिन रोजाना नए-नए मुद्दों को लेकर जूली के नेतृत्व में विपक्ष के सदस्य विधायक आवास से विधानसभा तक पहुंचे। इस दौरान विधायकों की नारेबाजी, विधायकों का हाथ में बैनर लेकर चलना और बैनर में अपनी डिमांड का उल्लेख करना, सरकार को कटघरे में खड़े करने जैसे नारे बैनर में अंकित करना, यह सब रोजाना

विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला, जो बिल्कुल नया और अद्भुत नवाचार था। रोजाना टीकाराम जूली नए-नए ज्वलंत मुद्दों और नए विषयों को लेकर विधायक आवास से प्रतिपक्ष के विधायकों को लेकर राजस्थान विधानसभा तक पहुंचते, उनका यह पैदल मार्च मीडिया में भी आकर्षण और सुर्खियों का केंद्र बना रहा, तो दूसरी तरफ प्रदेश की जनता में भी प्रतिपक्ष का यह पैदल मार्च चर्चा का विषय बना रहा।

शुरुआती पोलिटिकल के दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया पूरा सहयोग

टीकाराम जूली का राजनीति में फैमिली ग्राउंड नहीं था, लेकिन राजनीति के शुरुआती दिनों से ही कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में नजर आए। पार्टी के संगठन को अपने इलाके में गति देने और मजबूत करने में हमेशा आगे रहे। अपने मधुर और मिलनसार व्यवहार से दलित समाज ही नहीं, बल्कि उच्च जाति वर्ग के लोगों में भी काफी लोकप्रिय रहे, जिसकी वजह से अलवर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा को देखकर प्रभावित हुए। टीकाराम जूली की कड़ी मेहनत और लगन को देखकर सिंह ने जूली के पोलिटिकल कैरियर को काफी पुश किया और अब भी जूली और भंवर जितेंद्र सिंह के बीच बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल रिश्ते हैं।

हालांकि जूली और अशोक गहलोत के बीच भी मजबूत पॉलिटिकल रिश्ते हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा और जूली के बीच भी बहुत अच्छा पॉलिटिकल समन्वय और तालमेल बना हुआ है। डोटासरा और जूली दोनों एक दूसरे का काफी आदर और सम्मान करते हैं। अंता विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में जूली ने जो धांसू प्रचार किया, उसके बाद कांग्रेस को यहां जीत मिलने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा खुले मंच से जूली की अंता विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए की गई कड़ी मेहनत की तारीफ की। इसलिए यह तो जब जाहिर है कि राहुल गांधी के काफी भरोसेमंद नेता भंवर जितेंद्र सिंह का जूली के प्रति शुरू से ही काफी स्नेह रहा है और अब तक उनका जूली के प्रति स्नेह बरकरार है।

राहुल गांधी के वोट चोरी, मतदाता सूची शुद्धिकरण जैसे विषयों को लेकर काफी अलर्ट है जूली

चाहे बजट पर भाषण हो या फिर जनता से जुड़े मुद्दे हर विषय को बहुत ही शानदार ढंग से सदन में उठाया

प्रतिपक्ष का नेता बनने से पहले भी टीकाराम जूली की यह खासियत रही है कि कांग्रेस पार्टी की नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से नियमित रूप से प्रयास जारी रखे। जब विधायक और मंत्री थे, तब भी कांग्रेस पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार रखते थे और अब भी प्रतिपक्ष के नेता पद पर रहने के दौरान भी पार्टी के दिल्ली दरबार की ओर से जो जो कार्यक्रम राजस्थान कांग्रेस को दिए जाते हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर हमेशा गंभीर रहे। अभी हाल ही में राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी को लेकर देश भर में जो माहौल बनाया गया, उसमें इस मामले को लेकर टीकाराम जूली ने भी न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि प्रदेश भर में जहां-जहां उनकी सभाएं होती हैं, जहां-जहां उनके कार्यक्रम होते हैं, राहुल गांधी के इस मामले को लेकर तथ्यात्मक तरीके से लोगों को वोट चोरी के बारे में समझाते हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के मामले को लेकर जो हस्ताक्षर अभियान संपादित किया गया, इसमें भी टीकाराम जूली ने अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर करवाने में सफल रहे। इसके अलावा राजस्थान में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची शुद्धिकरण का जो कार्य संपादित किया जा रहा है, इस कार्य पर भी टीकाराम जूली का पूरा फोकस है। जूली उन नेताओं में से हैं, जो राजस्थान कांग्रेस और पार्टी हाई कमान के हर आदेश को गंभीरता से फॉलो करते हैं।

राजस्थान विधानसभा में चाहे प्रश्नकाल हो, या फिर किसी बिल पर मत व्यक्त करने की बात हो, या फिर बजट पर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भाषण देने की बात बात हो, या फिर बजट में अनुदान मांगों पर बहस हो, हर जगह हर विषय पर जूली ने राजस्थान विधानसभा में तथ्यात्मक तरीके से प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह कर सदन में सबको प्रभावित किया। जूली पूरी तैयारी के साथ विधानसभा आते हैं। जिस विषय पर जब विधानसभा में उन्हें बोलना होता है, उस विषय से जुड़ी तमाम तरह की छोटी बड़ी बातों का अध्ययन करके वह अपनी बात सदन में रखते हैं, इसलिए उनकी ओर से कहीं जाने वाली बातों को कोई गलत भी नहीं बता पाता, क्योंकि वे बाकायदा आंकड़ों और तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात कहते हैं। एक प्रखर वक्ता के रूप में जूली ने खुद को विधानसभा में साबित करके दिखाया। हालांकि यह पहली बार है, जब टीकाराम जूली विपक्ष में बैठे हैं, अन्यथा इससे पहले वर्ष 2008 और 2018 में जब वे विधायक चुने गए थे, तो बाकायदा गहलोत सरकार के इन दोनों ही कार्यकाल में मंत्री बने थे। इसलिए इस बार विपक्ष के तौर पर वह भी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में मौजूद रहना उनके लिए एक अलग सा नया अनुभव जरूर था, लेकिन उन्होंने इस नए अनुभव और नई बड़ी जिम्मेदारी को भी इस तरह से निभाया, जैसे वह पूर्व में कई बार प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हो। उनकी प्रतिपक्ष की भूमिका में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी अब तक देखने को नहीं मिली। यह बात अलग है कि अगर कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर, जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य भी हैं, अगर वे भी जूली को अपना आशीर्वाद दें, तो निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा में विपक्ष और भी दमदार तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। वैसे जूली ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायकों को एकजुट रहने, खासतौर से पार्टी के वे युवा विधायक जो पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं, उन्हें समय-समय पर सदन की कार्रवाई के बारे में अवगत करवाते रहते हैं। उन्हें राजस्थान विधानसभा के अंदर और राजस्थान विधानसभा के बाहर सदन के नियमों और कार्रवाई के बारे में जरूरी जानकारी देते रहते हैं। पार्टी के अपनी उम्र से बड़े विधायकों को पूरा सम्मान और आदर देते हैं, अपने से सीनियर पार्टी के विधायकों के सामने सर झुका कर नतमस्तक भी होते हैं। उनके इस व्यवहार की वजह से ही राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों का भी जूली को पूरा समर्थन और सहयोग मिला हुआ है।

सोशल मीडिया पर दमदार तरीके से दिखा रहे अपनी उपस्थिति

टीकाराम जूली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो अपने बयानों को लेकर रोजाना सुर्खियों में रहते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके बड़ी संख्या में फैंस हैं। सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर उनके बयान प्रसारित होते रहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं में ही नहीं, बल्कि प्रदेश भर के युवाओं में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। दलित समाज में तो पहले से ही उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर रोजाना किसी न किसी विषय को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर पलटवार करके कई तरह के सवाल पूछते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है, तो हाथों-हाथ ही सोशल मीडिया पर हादसे में हताहत होने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी प्रकट करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के स्तर पर कोई नया निर्णय या कोई कार्यक्रम बनाया जाता है, तो उसके बारे में भी हाथों-हाथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपना मैसेज प्रसारित करके अपने संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और पार्टी जनों तक भिजवाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जूली का अपना व्यक्तिगत सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी काफी मजबूत है, जिसके माध्यम से जूली राजस्थान सरकार की कमियों को तो उजागर करते रहते हैं, इसके अलावा अपने सुझाव भी देते रहते हैं, तथा किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को तो नियमित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते ही हैं। इसके अलावा प्रदेश में अपराध की घटनाओं, अवैध खनन, अवैध बजरी खनन, हथियार तस्करी, कानून व्यवस्था इत्यादि सभी विषयों को लेकर नियमित रूप से अपने बयान जारी करके संबंधित विभागों के अधिकारियों और राजस्थान सरकार को अलर्ट और सजक करते रहते हैं। इनका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट सुबह से लेकर देर रात तक सक्रिय रहता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।

पिता के पद चिन्ह पर बेटी, मंडावा को किया रोशन, हाई कमान ने दी बड़ी जिम्मेदारी

शेखावाटी के लोगों से अपने पिता की तरह हैं जमीनी जुड़ाव, पिछली दो गहलोत सरकार में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में करवाएं ऐतिहासिक विकास कार्य, वर्ष 2023 के चुनाव में भी दमदार हासिल की जीत, कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने झुंझुनू जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किया है नियुक्त।

जयपुर। प्रदेश के शेखावाटी अंचल में मंडावा विधायक रीटा का क्षेत्र के लोगों से जमीनी जुड़ा ठीक वैसा ही है, जैसा उनके पिता दिवंगत रामनारायण चौधरी का था। लोगों के इस जमीनी जुड़ाव के दम पर ही रीटा चौधरी वर्तमान में तीसरी बार मंडावा विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी यह कहना तो जल्दबाजी होगा कि रीटा अपने पिता की तरह कांग्रेस और प्रदेश की जनता में मुकाम हासिल कर पाएगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा की महिला होने के बावजूद भी उन्होंने अपने उतार-चढ़ाव के संघर्ष से भरे राजनीतिक जीवन में जिस खूबसूरती और समर्पित भाव से अपने पिता की विरासत को संभाला ही नहीं है, बल्कि अपने पिता के सपनों को साकार करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने में तन्मयता से आगे बढ़ रही हैं। उसी का परिणाम है कि हाल ही में कांग्रेस के दिल्ली दरबार में इन्हें झुंझुनू जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बिठाया है। झुंझुनू जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिलना अपने आप में यह दिखाता है कि कांग्रेस हाई कमान भी दिवंगत रामनारायण चौधरी की इस बेटी के परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं खुश और संतुष्ट है। इसी वजह से झुंझुनू जैसा जिला जो प्रदेश की राजनीति में खासतौर से जाट राजनीति में एक अलग वर्चस्व रखता है, इसकी कमान रीटा चौधरी के हाथों में दी। वह भी ऐसे समय में जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह पर कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस के प्रति पहले की तरह देश के लोगों में आकर्षण भी काफी कम हुआ है। साथ ही भाजपा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी एक बार फिर से जाट बहुल इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे हालातो में झुंझुनू जिले में कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के साथ कांग्रेस का विस्तार करना रीटा के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है, लेकिन यह भी सत्य है कि संगठन के मामलों में रीटा अपने पिता की तरह काफी निपुण और कुशल हो चुके हैं। पूर्व में भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करते हुए अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी यह उम्मीद है कि झुंझुनू जिले में कांग्रेस अब और भी मजबूती के साथ स्थापित होगी।

पिता की विरासत को शानदार तरीके से संभाले हुए हैं रीटा चौधरी

दिवंगत रामनारायण चौधरी शेखावाटी अंचल के ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नहीं माने जाते थे, बल्कि प्रदेश कांग्रेस के कर्मठ कुशल और योग्य दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी। चौधरी छह बार विधायक चुने गए, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान सरकार में अलग-अलग समय में मंत्री रहे और बड़े-बड़े विभाग इन्हें दिए गए। प्रदेश देश के बड़े जाट नेताओं में इनकी गिनती हुआ करती थी। इनके लोगों से जमीनी जुड़ाव और किसान नेता के रूप में इन की भूमिका को देखकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी चौधरी की काफी इज्जत किया करती थी। जब तक रामनारायण चौधरी जिए, तब तक राजस्थान कांग्रेस में उनका अच्छा वर्चस्व रहा। इस दौरान रीटा चौधरी अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की

पढ़ाई के दौरान अपने पिता के राजनीतिक कार्यों में उनका सहयोग करने लगी। अपने पिता का लोगों से जमीनी जुड़ाव को देखा और इस जमीनी जुड़ाव को दिल से अनुभव किया। अपने पिता के पार्टी के संगठन को मजबूती देने के प्रयासों में उनकी मेहनत और लगन को देखा। इसी तरह से अपने पिता को किसान और खेती के समुचित विकास के लिए अथक प्रयास करते देखा। यह सारे अनुभव और गुण उन्होंने अपने पिता की जीवन शैली और उनके साथ सामाजिक और राजनीतिक सरोकार के काम करते हुए हासिल कर लिए थे। यूं भी कह सकते हैं कि रीटा चौधरी ने अपने पिता के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करने के दौरान ही एक श्रेष्ठ राजनेता बनने की ट्रेनिंग भी एक तरह से कंप्लीट कर ली थी। शायद यही वजह है कि आज वह अपने पिता की तरह शेखावाटी के लोगों में निरंतर पॉपुलर हो रही हैं और एक मजबूत और ऊर्जावान महिला कांग्रेस नेता के रूप में खुद को स्थापित भी किया है। विधायक रहने के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में उल्लेखनीय विकास कार्य करवाए। वर्ष 2008 और 2018 में विधायक रहने के दौरान अपनी ही पार्टी सरकार होने का अपने क्षेत्र के विकास के लिए खूब फायदा उठाया। हालांकि वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान विधानसभा में अब तक जितनी भी बैठक हुई, उसमें अपने क्षेत्र की खारे पानी और किसान की समस्याओं को दमदार तरीके से उठाया। राजनीतिक विश्लेषक और क्षेत्र के लोग भी यह मानते हैं कि महिला होने के बावजूद भी रीटा में अपने पिता की तरह सर्वगुण संपन्न राजनेता के सारे गुण हैं, इसीलिए उनका क्षेत्र के लोगों में जमीनी जुड़ाव लगातार गहरा और मजबूत होता जा रहा है। राजनीति के जानकार लोग भी यह मानते हैं कि रीटा ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बहुत ही अच्छी तरह से संभाले हुआ है।

मंडावा विधानसभा क्षेत्र में रीटा चौधरी की ओर से किए उल्लेखनीय कार्यों की है लंबी सूची

वर्ष 2008 में रीटा चौधरी पहली बार मंडावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। उस समय इनके पिता जीवित थे, टिकट दिलवाने से लेकर रीटा चौधरी की जीत में इनके पिता की बड़ी भूमिका रही। लेकिन विधायक बनने के बाद रीटा चौधरी ने अपने पिता की तरह खुद को पॉलिटिक्स में तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने निरंतर क्षेत्र के लोगों से संवाद जारी रखा। पिता की आयु अधिक होने और उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखकर रीटा चौधरी ने राजनीति का पूरा वजन अपने कंधों पर लिया। एक तरफ उनके सामने पिता की विरासत को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती थी, तो दूसरी तरफ मंडावा क्षेत्र के लोगों के भरोसे को भी जिंदा रखना था। इसलिए उन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र की सालों की गंभीर समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। यह उनकी खुशकिस्मत थी कि 2008 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिसकी वजह से उन्हें अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में ज्यादा कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। इस बीच 2012 में अपने पिता के निधन का उन्हें गहरा झटका भी लगा, क्योंकि उनके पिता एक तरह से राजनीति के सबसे बड़े गुरु थे, जिनके मार्गदर्शन और अगुवाई में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू की। इसलिए पिता के निधन से रीटा चौधरी अंदर से दुखी तो खूब हुई, लेकिन पिता के अधूरे सपनों को पूरे करने का ख्वाब और पिता की विरासत को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ने रीटा चौधरी को एक मजबूत राजनेता बनने की ओर प्रेरित किया। वर्ष हालांकि 2008 के कार्यकाल में रीटा चौधरी ने अपने क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या के निवारण के लिए कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का मामला जोर-जोर से उठाया, जिसे तत्कालीन गहलोत सरकार ने मंजूर भी कर लिया था, लेकिन बाद में 2013 में प्रदेश में भाजपा की सरकार के गठन के बाद यह परियोजना कागजों से निकलकर धरातल पर नहीं आ सकी। हालांकि वर्ष 2008 में अन्य आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, चिकित्सा, बिजली, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में रीटा चौधरी ने अपने स्तर पर प्रयास करके व्यापक कार्य करवाए, लेकिन 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने की वजह से रीटा ने निर्दलीय चुनाव लडा और कड़े मुकाबले में मामूली वोटो के अंतर से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी और 2013 के विधानसभा चुनाव में 200 में से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 21 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर चुनाव हार गए थे, लेकिन इन चुनाव में रीटा चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भारी संख्या में वोट हासिल किए थे। बाद में 2018 में कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें फिर से टिकट दिया गया और अच्छे वोटो के अंतर से रीटा चौधरी दूसरी बार इस सीट से विधायक चुनी गई। इस तरह से 2008 और 2018 इन दो विधानसभा चुनाव में अपने विधायक पद के कार्यकाल में इन्होंने बड़ी संख्या में विकास कार्य करवाए, जिसमें पूरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में जहां पहले एक उप तहसील हुआ करती थी, वहां इन्होंने तीन तहसील स्थापित करवाई। मलसीसर, बिसाऊ और मंडावा में तीन तहसील कार्यालय खुलवाए। इसी तरह से दो जगह पर पंचायत समिति कार्यालय खुलवाएं, दो जगह पर एसडीएम के दफ्तर खुलवाएं, क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करवाई, वेटरनरी कॉलेज आईआईटी केंद्र खुलवाया, क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खुलवाएं, महिला कॉलेज की स्थापना करवाई। इस तरह से व्यापक स्तर पर इन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए। उसी का नतीजा है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकांश मंत्री और कई बड़े नेता चुनाव हार गए, लेकिन मंडावा से रीटा चौधरी ने शानदार जीत दर्ज की। अपने दोनों ही कार्यकाल में इन्होंने अपने क्षेत्र में हर गांव तक नई सड़कों का जाल बिछाया, क्षेत्र में उप जिला अस्पताल की भी स्थापना करवाई, आधा दर्जन कॉलेज की स्थापना करवा कर शिक्षा के क्षेत्र में मंडावा को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। जानकार लोगों का कहना है कि मंडावा निर्वाचन क्षेत्र में रीटा चौधरी की ओर से बड़े पैमाने पर करवाए गए विकास कार्यों की वजह से ही आज इस निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ खेती के लिए पानी की बड़ी समस्या है, अन्यथा और सभी बड़ी समस्याओं से मंडावा निर्वाचन क्षेत्र करीब-करीब मुक्त हो गया है। मंडावा के विकास की यह जो नई तस्वीर सामने आई है, इसमें स्थानीय विधायक रीटा चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है।

अनुशासन, लोगों से जमीनी जुड़ाव, पार्टी के प्रति समर्पण भाव देखकर ही कांग्रेस हाई कमान ने दी है बड़ी जिम्मेदारी

जानकार लोगों का कहना है कि हाल ही में रीटा चौधरी को झुंझुनू जिला कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद मिला है, वह उन्हें उनकी योग्यता, पार्टी के प्रति समर्पित भाव से होकर कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति, लोगों से उनका गहरा जमीनी जुड़ाव, अनुशासित जीवन और खुद को पार्टी की गुटबाजी से दूर रहने की प्रवृत्ति के कारण ही मिला है। इसके अलावा अब से पहले पार्टी ने संगठन में इन्हें जो भी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से बखूबी से निभाया। अब से पहले राजस्थान महिला कांग्रेस के संगठन में भी विभिन्न पदों पर रहने के दौरान अच्छा कार्य किया। वर्ष 2002 में राजस्थान महिला कांग्रेस में सचिव, वर्ष 2004 में राजस्थान महिला कांग्रेस में महासचिव के अलावा राजस्थान कांग्रेस कमेटी में सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी लंबे समय से कार्य करने के दौरान संगठन से जुड़े सभी छोटे-बड़े विषयों की अच्छी जानकारी रखती हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि चाहे संगठन में इन्हें जिम्मेदारी मिली हो या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के विस्तार को गति देने और संगठन की मजबूती के लिए इनको हमेशा सतत प्रयास रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पार्टी में खुद को गुटबाजी से दूर रखती हैं। सौम्य, सरल और शालीन रहने के साथ-साथ जरूरत पड़ने बड़े-बड़े जन आंदोलन की अगवाई की और राजस्थान विधानसभा में भी दमदार तरीके से हमेशा अपनी बात रखी। इसलिए इनके जुझारू और ऊर्जाशील रवैया को देखकर ही प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने इन्हें एक महत्वपूर्ण जिले में पार्टी की बागडोर दी है। राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि झुंझुनू जिले में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती देने में इस महिला नेता के सामने कई बड़ी चुनौतियां और परेशानी जरूर सामने आ सकती हैं, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही इनके पिता अभी जीवित नहीं हो, लेकिन इनके पिता की अच्छी छवि आज भी शेखावाटी के लोगों के दिलों में बसी हुई है, उसका भी इन्हें अच्छा पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा रीटा ने अब खुद भी एक मजबूत और समर्पित जन नेता की तरह खुद को साबित किया है। अपने विधायक कार्यकाल में अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों से अपने क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे झुंझुनू जिले में अपनी एक अलग महिला जाट नेता के रूप में पहचान बनाई है। इसलिए अब यह जो नई बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसको बखूबी से निभाने की इनमें पूरी क्षमता है। इसलिए राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले लोगों का भी मानना है कि झुंझुनू जिले के छोटे बड़े सभी कांग्रेस जनों को एक मंच पर लाने में रीटा चौधरी को सफलता जरूर मिलेगी।

भजनलाल सरकार के कार्यकाल में भी विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को दमदार तरीके से उठाया

प्रदेश की वर्तमान भजनलाल सरकार के कार्यकाल में राजस्थान विधानसभा के अब तक जितने भी सत्र आयोजित हुए हैं, इन सभी सत्र में रीटा चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को दमदार तरीके से उठाया। रीटा चौधरी का व्यवहार विधानसभा में बिल्कुल अनुशासित, संयमित और काफी सरल रहता है, लेकिन जब इन्हें बोलने का मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोरदार तरीके से सदन में रखती हैं। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ही इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में झींगा फार्मिंग को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया और कहा कि क्षेत्र में खारे पानी की वजह से अन्य फसल होना काफी मुश्किल है, इसलिए किसान झींगा फार्मिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए सरकार को झींगा फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर और प्रयास करने चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने इस बात पर आक्रोश प्रकट किया कि झींगा फार्मिंग में बिजली विभाग की ओर से किसानों को व्यवसायिक बिजली की दर के आधार पर बिल भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है और भारी बिल आने की वजह से किसानों का आर्थिक संकट काफी बढ़ गया है। चौधरी ने भजनलाल सरकार से डिमांड की कि झींगा फार्मिंग से जुड़े किसानों को बिजली के बिल में रियायत दी जाए। किसानों को व्यावसायिक तरीके से बिल भेजना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के किसान पहले ही खारे पानी की वजह से खेतों में फसल नहीं उगा पा रहे, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक हालत पहले से ही काफी खराब है। और अब अगर किसान खुद की हालत सुधारने के लिए झींगा फार्मिंग को अपना रहे हैं, तो सरकार को भी उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। रीटा चौधरी ने झींगा फार्मिंग से जुड़े किसानों को तुरंत बिजली का कनेक्शन देने की भी मांग की। वैसे कहा जा रहा है कि रीटा चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की अन्य बहुत सी बड़ी-बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निवारण उन्होंने वर्ष 2008 और 2018 के अपने विधायक पद के कार्यकाल में करवा लिया था। क्योंकि इन दोनों ही कार्यकाल में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसलिए अपनी ही पार्टी की सरकार से अपने क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास कार्य करवा लिए थे, जिसमें सालों से लंबित समस्याओं का भी उन्होंने निवारण करवाया था। क्षेत्र में पीने के पानी की जो बड़ी समस्या थी, उस

समस्या का निवारण उन्होंने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का शुभारंभ करवा कर इस परियोजना को जल जीवन मिशन से जुड़वाया, जिसका लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन यहां खारे पानी की वजह से खेतों में अच्छी फसल पैदा करना किसान के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, इसलिए यहां के किसान झींगा फार्मिंग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

जाट समाज में महिला राजनेताओं में अग्रिम पंक्ति में नजर आती हैं रीटा चौधरी

जानकार लोगों का कहना है कि जाट समाज में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों में पुरुष नेताओं की तो लंबी लिस्ट है, लेकिन महिला नेताओं में काफी कमी है। कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही एक से एक बड़े से बड़े जाट नेता रहे हैं, लेकिन जाट समाज में महिला नेताओं की हमेशा कमी रही। लेकिन अब धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी में महिला जाट नेताओं का दबदबा नजर आने लगा है। रीटा चौधरी, कृष्णा पूनिया जैसे महिला नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी में महिला जाट नेताओं की उपस्थिति दमदार तरीके से नजर आने लगी है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और राजस्थान में भी मतदाताओं में आधी जनसंख्या महिलाओं की है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छात्राएं आजकल मतदान में जबरदस्त रुचि दिखाने लगी हैं। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी लड़कियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और छात्र संघ में अपनी उपस्थिति भी दमदार तरीके से दिख रही हैं। इसलिए राजस्थान कांग्रेस में महिला जाट नेता प्रदेश की महिलाओं और कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए अब रीटा चौधरी और कृष्णा पूनिया जैसी महिला जाट नेताओं के दम पर प्रदेश की महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सकता है, क्योंकि फील्ड में महिलाओं के बीच महिला नेता ही महिलाओं को अच्छी तरह से समझाने में सफल होती है और महिलाएं भी महिलाओं की बात को ही ज्यादा तवज्जो देती हैं। इसलिए राजस्थान कांग्रेस और कांग्रेस हाई कमान अब महिलाओं को ज्यादा अवसर और ज्यादा मौका देने के बारे में गंभीरता से कार्य करने लगा है। उसी का नतीजा है कि रीटा चौधरी को झुंझुनू जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई। इसमें कोई दो राय नहीं, भले ही रीटा चौधरी महिला हो, लेकिन वे अब एक कुशल और पारंगत राजनेता बन चुकी है। जिले की महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए उनकी ओर से आने वाले दिनों में अपने स्तर पर नए नवाचार और नए प्रयोग भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीटा चौधरी भले ही अनुशासित और सरल दिखती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर जब वह हमला बोलते हैं तो फिर उनके भाषण काफी दमदार और सटीक होते हैं। वे बिना किसी डर और संकोच के अपनी बात कहती हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं। इसलिए यह राजस्थान के जाट समाज के लिए भी बड़े गर्व का विषय है कि उन्हें की समाज की एक दबंग और ऊर्जावान महिला को झुंझुनू जैसे जिले में पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिली।

उच्च शिक्षित हैं रीटा चौधरी, जनसेवा के लिए अच्छी सैलरी की नौकरी छोड़ी

रीटा चौधरी ने अपनी कंप्लीट पढ़ाई जयपुर में की है। राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर, अंग्रेजी साहित्य में भी स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय से ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड हुमन रिसर्च में स्नाकोत्तर डिप्लोमा, इसके अलावा न्यू फोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया बेंगलुरु से कार्मिक प्रबंधन में एमबीए की डिग्री भी हासिल की हुई है। स्कूल के समय से ही पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट, जिसके कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छे अंकों से इन्होंने सभी बड़ी डिग्री हासिल की, जिसके फल स्वरुप इन्हें एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अपने पिता के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अपने पिता को जन सेवा के कार्यों के लिए समर्पित देखकर खुद के मन में भी इसी तरह से ग्रामीण परिवेश में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और किसान की पीड़ा को दूर करने के जज्बे ने राजनीति में कदम रखने को मजबूर कर दिया। जब पिता रामनारायण चौधरी ने अपनी बेटी को अपने साथ इस तरह से जन सेवा के कार्यों में समर्पित भाव से कार्य करते हुए देखा, तो उन्होंने यह सोच लिया था कि उनकी यह बेटी उनके नाम को आगे बड़े ही शान से बढ़ाएगी। इसलिए रामनारायण चौधरी ने भी रीटा चौधरी की इच्छा को दबाया नहीं, बल्कि अपनी बेटी की प्रतिभा और लगन को देखकर उसे कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी के विस्तार के लिए पार्टी से जोड़ लिया। और खुद के अधिक आयु होने और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा और अपनी बेटी रीटा को 2008 के विधानसभा चुनाव में मंडावा से कांग्रेस का टिकट दिलवाया, जिसमें उन्हें जीत भी मिली। इस तरह से अपने पहले ही चुनाव में रीटा ने सफलता हासिल की।

सिर्फ अपने काम से मतलब गुटबाजी से कोई लेना-देना नहीं

दिग्गज जाट नेता रामनारायण चौधरी जब तक जीवित रहे और जब तक राजस्थान कांग्रेस में रहे, उन्होंने अपने सिद्धांतों के हिसाब से राजनीति की। किसी के दबाव में नहीं आए और ना ही किसी की चापलूसी की। ठीक उसी तरह की पॉलीटिकल यात्रा अब तक की रीटा चौधरी की रही है। अपने पिता की तरह सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों और पार्टी के संगठन को गति देने जैसे कार्यों पर ही पूरा फोकस रखती हैं। पार्टी में आपस में बड़े नेताओं के बीच चल रही लड़ाई के बीच खुद को इस लड़ाई से अलग रखती हैं और चुपचाप अपने पिता की तरह सिद्धांतों की राजनीति करते हुए समर्पित भाव से कांग्रेस पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिलती है, उसको बखूबी से निभाती हैं। यही उनकी खासियत है और इनकी इस खासियत से राजस्थान कांग्रेस के बड़े लीडर ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता भी अच्छी तरह से वाकिफ है। खुद के स्वाभिमान को जिंदा रखा है और अपनी मेहनत, लगन और अपने जनता के जुड़ाव के आधार पर शेखावाटी क्षेत्र के लोगों पर अपनी पकड़ को निरंतर मजबूत बनती जा रही है।

विराट नगर को अपराध और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने में जुटे कुलदीप धनकड़

विधानसभा के विभिन्न सत्र में विभिन्न विषयों, बजट भाषण और विभिन्न अनुदान मांगों की चर्चा में अपने सटीक और तथ्यात्मक भाषण से सत्ता पक्ष के लोगों का जीता दिल, अपने निर्वाचन क्षेत्र की सालों से लंबित गंभीर समस्याओं के निवारण के लिए कर रहे सतत प्रयास, बजट में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य मंजूर करवाने में हुए सफल।

जयपुर। इसे विराटनगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बदकिस्मती ही कहीं जाएगी कि जो क्षेत्र महाभारत कालीन युग से अपनी अलग पहचान रखता है, जो क्षेत्र कभी पांडवों की राजधानी हुआ करता था और जो क्षेत्र सम्राट अशोक की यादों से जुड़ा हुआ है, वह क्षेत्र अब तक विकास के मामले में काफी पीछे रहा। इसे चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहें या फिर स्थानीय लोगों का अपने अधिकारों और हक के लिए चौकस नहीं रहना कहें, बात चाहे कुछ भी हो वास्तविकता यह है कि ऐतिहासिक विराटनगर समुचित और सर्वांगीण विकास के मामले में प्रदेश के अन्य आसपास के निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में काफी पीछे रहा। इसीलिए स्थानीय लोगों का राजनेताओं के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं रहा। इस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायक चुने गए, इनमें कुछ राजस्थान सरकार के मंत्री भी बने। इसके अलावा यह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, इसलिए यहां से चुने गए सांसद केंद्र सरकार में कई बार मंत्री भी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी विराटनगर का समुचित विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को यहां अब भी कई तरह की गंभीर समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में यहां कार्य हुए हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं होने से जो कार्य हुए हैं, उनका असर साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने के बाद पिछले 2 साल में विराटनगर निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर तेजी से हल चलें देखने को मिली है। स्थानीय भाजपा विधायक कुलदीप धनकड़ की सक्रियता से भजनलाल सरकार में अब तक जितनी बार भी राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किए गए, उन बजट में विराटनगर क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मंजूर करवाने में धनखड़ काफी कामयाब रहे हैं। इसलिए इस बार क्षेत्र के लोगों को यह उम्मीद जगी है कि शायद अब विराटनगर क्षेत्र के दिन सुधर जाएं। हालांकि पिछली गहलोत सरकार के दौरान सड़क के क्षेत्र में कार्य हुए, लेकिन पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, उद्योग जैसे क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर लोगों में कोई ज्यादा खुशी देखने को नहीं मिलती। लोगों का यही कहना है कि उनकी परंपरागत गंभीर समस्याएं उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किए हुए हैं, तो फिर ऐसी हालातो में इन नई सड़कों का सुख उन्हें कैसे नसीब हो। लेकिन पिछले 2 साल में स्थानीय विधायक कुलदीप धनकड़ ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राजस्थान विधानसभा में ही आवाज नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक जोरदार तरीके से क्षेत्र के समस्याओं को उठाया। उसी का परिणाम रहा की पिछले 2 साल विराटनगर क्षेत्र के विकास के लिए काफी अच्छे साबित हुए। अपराधों पर अंकुश तो लगा ही है, इसकेअलावा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण और नई सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए सरकार से मंजूर करवाने में धनखड़ सफल रहे। इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, बिजली कनेक्शन क्षेत्र में भी विकास कार्यों का सिलसिला तेजी से चल पड़ा है, जिन्हें देखकर स्थानीय लोगों के चेहरों पर थोड़ी चमक जरूर नजर आने लगी है। अभी भजनलाल सरकार के करीब 3 साल का समय बाकी है और पिछले 2 साल में स्थानीय विधायक धनखड़ की सक्रियता से लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 3 साल भी विराटनगर के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि धनखड़ ने पिछले 2 साल में क्षेत्र के विकास के लिए जो सक्रियता और तत्परता दिखाई, आने वाले 3 साल में उनकी सक्रियता और तत्परता आगे कितनी गति पकड़ेगी। फिलहाल धनखड़ ने अब तक के कार्यकाल में यहां जो कार्य किए हैं, उनसे स्थानीय लोग संतुष्ट और खुश हैं।

अपराध मुक्त होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा विराटनगर

पिछले कई सालों से विराटनगर अपराध के मामलों में काफी सुर्खियों में रहा। पिछली गहलोत सरकार के दौरान यहां कई बड़े-बड़े गोलीकांड हुए। व्यापारियों के साथ मारपीट, हफ्ता वसूली और लूट जैसी गंभीर अपराध की घटनाओं ने यहां के लोगों को काफी भयभीत और परेशान रखा। खासतौर से व्यापारियों में हमेशा डर बना रहता था। स्थानीय गुंडा गैंग से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों के बदमाशों की बढ़ती सक्रियता ने स्थानीय जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। ऐसा नहीं है कि पिछले गहलोत सरकार के दौरान ही यहां पर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, बल्कि इससे पहले वर्ष 2008 और 2013 इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के फूलचंद भिंडा विधायक थे, उस समय भी यहां अपराध की घटनाएं लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई थी। लेकिन पिछली गहलोत सरकार के दौरान विराट नगर में अन्य राज्यों के गुंडा गैंग की सक्रियता काफी बढ़ गई थी, इसकी वजह से यहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। व्यापारी वर्ग हमेशा डरे नजर आते थे। राजस्थान विधानसभा में भी गहलोत सरकार के समय अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य काफी चिंता प्रकट किया करते थे, लेकिन तत्कालीन विधायक इंद्राज गुर्जर अपनी पार्टी की सरकार के रहते हुए भी यहां पर अपराधों पर अंकुश लगाने में ज्यादा सफल नहीं रहे। गुर्जर पहली बार के विधायक थे और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के आपस की लड़ाई में वह भी फस गए थे, जिसका असर विराटनगर के विकास कार्यों पर भी पड़ा। राजस्थान पुलिस के अपराध के आंकड़ों पर भी नजर डालें, तो निश्चित रूप से गहलोत सरकार के समय प्रदेश में अपराध के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई थी और विराट नगर भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। लेकिन वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने के बाद और विराटनगर में भाजपा के कुलदीप धनकड़ के विधायक चुने जाने के बाद, धनखड़ ने यहां पर सबसे पहले इलाके में अपराधों पर अंकुश लगाने के काम पर ज्यादा फोकस किया, ताकि लोगों के चेहरे पर अपराधियों को लेकर जो चिंता की लकीरें छाई रहती है, वह लकीरें मिट सके। धनखड़ ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी लोगों से वादा किया था कि वे विराटनगर क्षेत्र को पूरी तरह से अपराध मुक्त बनाएंगे। इस कार्य में उन्हें अब काफी सफलता भी मिली है। यह भी सही है कि प्रदेश में पिछले दो साल में अपराधों के आंकड़ों में भी गहलोत सरकार के अपराधों की तुलना में काफी गिरावट आई है और यह गिरावट विराटनगर क्षेत्र में भी देखने को मिली है। एक समय ऐसा था जब विराटनगर में गोलीकांड होना आम बात हो गई थी, लेकिन पिछले 2 साल में विराटनगर में कोई बड़ी अपराध की घटनाएं देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग खुश भी हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि धनखड़ यहां नियमित रूप से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं। उन्हें इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तो देते ही हैं, इसके अलावा इलाके में पुलिस स्टेशन स्तर पर, बीट स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के संदर्भ में धनखड़ स्थानीय लोगों को भी पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए कहते हैं। सीएलजी मेंबर, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ भी धनखड़ नियमित रूप से बातचीत और संवाद करके इलाके में अमन चैन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के सतत प्रयास करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा इलाके में पुलिस की दिन और रात की निगरानी को प्रभावी ढंग से संपादित हो, इसके लिए भी बड़े अधिकारियों से नियमित रूप से संवाद करते रहते हैं, जिसका सीधा असर पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली पर और कार्यशैली पर भी पड़ा है। पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस की व्यवस्थाओं में काफी कुछ सुधार और नवाचार हुआ है। इन सब की वजह से यह निर्वाचन क्षेत्र जो पहले अपराध की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहता था, अब पिछले दो साल से यहां लूट, डकैती, नकबजनी, हफ्ता वसूली, हत्या जैसीगंभीर अपराध की घटनाएं देखने को नहीं मिली, जिसका पूरा श्रेय स्थानीय विधायक धनखड़ को दिया जा रहा है। क्योंकि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुलदीप धनकड़ नियमित रूप से पुलिस प्रशासन, स्थानीय व्यापारियों, सामाजिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित करते रहते हैं। आपस की सूझबूझ और आपस के सामूहिक प्रयास से ही इस इलाके में पुलिस को अपराधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिली।

विराट नगर में औद्योगिक माहौल बनाने के कुलदीप धनकड़ के सतत प्रयास

विराट नगर निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या सालों से बनी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही और इस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायक भी चुने गए। यहां से चुने विधायक राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, तो सांसद केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन विराटनगर इलाके में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कोई भी नहीं निकल पाया। हालांकि सरकारों ने इलाके में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा जरूर की, लेकिन यह घोषणा सिर्फ कागजी घोषणा साबित हुई। हकीकत में यहां बड़े उद्योगों की स्थापना की बात तो दूर, लघु, मध्य और कुटीर उद्योग धंधों से जुड़ी एक भी इकाई की स्थापना नहीं हुई, जिसकी वजह से विराटनगर इलाका औद्योगिक क्षेत्र के मामले में पूरे प्रदेश में काफी पीछे रहा। स्थानीय लोगों की भी यही पीड़ा रही कि अगर यहां पर थोड़े बहुत भी कुछ नए उद्योग धंधे खुल जाते, कुछ फैक्ट्रियां खुल जाती, तो स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाता। जबकि इलाके में जमीन प्रचुर मात्रा में है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। सरकार चाहे तो यहां पर व्यापक पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर सकती है, लेकिन यह विराटनगर के लोगों की बदकिस्मती ही है कि प्रचुर मात्रा में जमीन होने के बाद भी यहां उद्योग धंधे नहीं खुल पाए। बताया गया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, जो या तो अन्य शहरों में जाकर छोटा-मोटा रोजगार और मजदूरी करते हैं या फिर मन मार कर अपनी खेती के कार्य को संभाल रहे हैं। जानकार लोगों का कहना है कि अगर यहां पर बहुत पहले ही औद्योगिक माहौल बना दिया जाता, तो अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार यहां अपने आप ही हो जाता। लेकिन यहां छोटे-मोटे उद्योग भी स्थापित नहीं किए गए, जिसकी वजह से दूर-दूर तक सिर्फ खाली जमीन वीरान सी नजर आती है। तकलीफ वाली बात यह है कि यहां सरकारों की ओर से रीको एरिया भी घोषित किया हुआ है, लेकिन इस घोषणा को क्रियान्वित नहीं किया गया। अगर इसके क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि सक्रिय होते, तो शायद उद्योगों के खुलने का सिलसिला भी शुरू होता। लेकिन पूर्व के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में विराटनगर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरह से प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में बड़ी संख्या में 35 लाख करोड़ के समझौते किए हैं, इन समझौते के क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहे हैं। एक-एक समझौते को लागू करने के लिए निवेशकों को जमीन का आवंटन भी किया जा रहा है। आगामी दिसंबर माह में प्रदेश में प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह का भी आयोजन हो रहा है। इन सब के बीच स्थानीय विधायक कुलदीप धनकड़ ने भी विराटनगर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए सतत रूप से प्रयास शुरू किए हैं। धनखड़ किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार युवाओं की मनोदशा को भी अच्छी तरह से जानते हैं और वह यह भी जानते हैं कि विराटनगर में एक अच्छा औद्योगिक माहौल तैयार करके क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध करवाई जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने विराटनगर क्षेत्र में औद्योगिक माहौल विकसित करने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। उनका प्रयास है कि राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह के तहत अगर विराटनगर में कुछ बड़े औद्योगिक संस्थान खुल जाएं, तो फिर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की तकदीर भी खुल जाए। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत भी की। बताएं, जानकार लोगों का कहना है कि उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व में जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं, इसलिए विराटनगर क्षेत्र के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। ऐसे में अब यह उम्मीद की जा रही है कि जिस तत्परता से धनखड़ अपने क्षेत्र में नई फैक्ट्री की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह भी ताकत देंगे, तो निश्चित रूप से विराटनगर में भी नई औद्योगिक इकाइयां बहुत जल्दी स्थानीय लोगों को देखने को मिल सकती है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खुलकर की तारीफ, सरकार के 2 साल के कार्यों को बताया ऐतिहासिक

विधायक कुलदीप धनकड़ प्रदेश भाजपा के पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में प्रवक्ता हैं, इसलिए उनके भाषण शैली और उनके बोलने का अंदाज हमेशा प्रभावित रहा है। जो भी बात बोलते हैं, तथ्यात्मक तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करके अपने भाषण को हमेशा वजनदार बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा में भी चाहे विभिन्न अनुदान की मांगों पर चर्चा की बात हो या बजट पर बहस हो या फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र की कोई डिमांड की बात हो, हर विषय पर उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात अब तक राजस्थान विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में उठाई है। उन्होंने न केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की बातों को विधानसभा में उठाया, बल्कि प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट और सरकार की ओर से अब तक किए गए विभिन्न कार्यों और उपलब्धियां का तथ्यात्मक तरीके से विवरण प्रस्तुत करके विपक्ष के नेताओं की जुबान को बंद करने का प्रयास किया। विधानसभा के अब तक जितने भी सत्र हुए हैं और जितनी भी बैठक हुई है, उनमें सत्ता पक्ष की ओर से हर बड़े विषय पर धनखड़ को बोलने का अवसर दिया गया। वजह यही है कि हर विषय पर धनखड़ पूरी स्टडी के साथ विधानसभा में आते हैं और फिर आंकड़ों के माध्यम से तथ्यात्मक तरीके से विषय पर जानकारी प्रस्तुत करके अपनी बात रखते हैं। इसलिए उनकी बातों को और उनके भाषण को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य ध्यान पूर्वक सुनते भी हैं। लेकिन कई बार अपने भाषण के दौरान कुलदीप धनकड़ कांग्रेस की सरकारों और कांग्रेस के नेताओं पर मर्यादित टीका टिप्पणी करने से भी नहीं चूकते, जिसकी वजह से उनकी बातों को लेकर कई बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा भी किया। लेकिन धनखड़ की खासियत यह है कि वह अपने भाषण में शब्द की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में खुले दिल और खुले दिमाग से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खूब तारीफ की। मुख्यमंत्री शर्मा की ओर से पानी के क्षेत्र में लिए गए बड़े-बड़े फैसले और निर्णय से उन्होंने भजनलाल शर्मा को भागीरथ ऋषि तक का दर्जा दिया और उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत और उनकी सोच को सेल्यूट करके उन्होंने विधानसभा में यहां तक कहा कि पिछले 2 साल में भजनलाल सरकार ने जो कार्य किए हैं, ऐसे कार्य राजस्थान के इतिहास में इतने कम समय में इससे पहले किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। उन्होंने बाकायदा भजनलाल सरकार और पिछली गहलोत सरकार की ओर से सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, किसान की ऋण माफी, सहकारिता, रोजगार जैसे मामलों में किए गए कार्यों की तुलना करते हुए तथ्यात्मक तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करके सटीक जानकारी देकर यह बताने का प्रयास किया कि भजनलाल सरकार ने पिछले 2 साल में ही जो कार्य किए हैं, इतने कार्य पिछली गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल में नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं और विकास से जुड़े विषयों को भी प्रभावी ढंग से रखा। उसी का नतीजा रहा कि विराट नगर निर्वाचन क्षेत्र को भजनलाल सरकार के हर बजट में अच्छी सौगात मिली।

पार्टी के संगठन से जुड़े विषयों पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं धनखड़

कुलदीप धनकड़ की गिनती भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बारीकी से अच्छी जानकारी रखने वाले नेताओं में होती है। धनखड़ पूर्व में प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता पद पर तैनात हैं। इसलिए पार्टी के संगठन से जुड़े विषयों पर बहुत पहले से ही उनकी अच्छी पकड़ रही है और संगठन को गति देने में भी अब तक अच्छी पकड़ रही है। इस बात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि शर्मा भी खुद करीब 20 साल तक प्रदेश भाजपा के महामंत्री रहे हैं। इसलिए पूर्व में मुख्यमंत्री शर्मा के साथ कुलदीप धनकड़ ने पार्टी के संगठन में मिलकर अच्छा कार्य किया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शर्मा और धनखड़ दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे की खूबियों को अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे का काफी आदर और सम्मान भी करते हैं। जिसका फायदा कुलदीप धनकड़ ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सरकार से विकास कार्यों की सौगात लेकर उठाया भी है। कुलदीप धनकड़ जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए प्रदेश भाजपा के जाट समाज के नेताओं में अग्रिम पंक्तियों में इनका भी नाम आता है। कुलदीप धनकड़ जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रहने के कारण किसानों की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते भी हैं। ग्रामीणों के बीच में हमेशा रहते हैं, इसलिए किसान और ग्रामीण परिवारों की समस्याओं से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। प्रदेश में पिछली गहलोत सरकार के शासनकाल के दौरान विराटनगर क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, धरने, जुलूस, रैली और जन आंदोलन के माध्यम से क्षेत्र की लोगों की आवाज बन रहे। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर नाराज भी हुए और पार्टी छोड़ने का मन भी बनाया। लेकिन इनकी अंदरूनी आत्मा भाजपा छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि पार्टी के संगठन को मजबूती देने में इन्होंने खुद सालों तक कड़ी मेहनत की। ऐसे में इस मुकाम पर आकर पार्टी को छोड़ना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि विराट नगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पार्टी के संगठन को मजबूती देने में धनखड़ का सबसे बड़ा योगदान रहा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर भाजपा के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम नियुक्त की। इस टीम को चुनाव की जिम्मेदारी देने के अलावा केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां और अच्छे कार्यों के प्रचार प्रसार के अलावा और प्रदेश भाजपा की ओर से जारी आदेशों की पालना के लिए भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। धनखड़ पार्टी से ज्यादा से ज्यादा नए युवाओं को जोड़ने में भी काफी सफल रहे। धनखड़ के बारे में कहा जाता है कि नए युवा वर्ग को कैसे और किस तरह से जोड़ा जाए, इसकी कला में धनखड़ काफी निपुण है। इसलिए पार्टी के संगठन से जुड़े छोटे-बड़े सभी विषयों में धनखड़ काफी निपुण है। इसीलिए इन्हें प्रदेश भाजपा के महामंत्री पद पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस जिम्मेदारी को भी इन्होंने बहुत शानदार तरीके से निभाया और पार्टी ने जहां भी जो भी जिम्मेदारी दी, उसमें ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करके प्रदेश भाजपा के नेताओं को ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी काफी प्रभावित किया। यहां तक की प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी धनखड़ के कार्यों से हमेशा प्रभावित रहे।

सचिन की पुलिस कमिश्नरेट में दूसरी पारी का शानदार आगाज

बीजू जार्ज जोसेफ के पुलिसिंग में किए गए नवाचारों को गति देने के साथ-साथ खुद के नवीन प्रयोग और नवाचारों से संगठित अपराधों, साइबर क्राइम जैसे अपराधों को जड़ से मिटाने की तैयारी।

जयपुर। निश्चित रूप से बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर पुलिस के श्रेष्ठ कप्तान साबित हुए। उनकी जगह जयपुर के पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्त हुए सचिन मित्तल को अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन उनकी ओर से कम समय में ही बेस्ट पुलिसिंग के लिए जो कदम अब तक उठाए गए हैं, उनसे ऐसा दिख रहा है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में सचिन की यह दूसरी पारी काफी ऐतिहासिक और यादगार हो सकती है। क्योंकि 1996 से अब तक की आईपीएस की सर्विस में सचिन मित्तल ने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी को बहुत ही शानदार ढंग से निभाया। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, जिसकी वजह से इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला। इनकी गिनती अनुशासित, ईमानदार और कर्मठ आईपीएस अफसर में होती है। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने फील्ड पोस्टिंग में लंबा समय बिताया, इसलिए अलग-अलग जिलों में पुलिस अधीक्षक पद की नौकरी के दौरान अलग-अलग तरह के अपराध और अपराधियों से सामना करना पड़ा। इसलिए अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को दबोचने में यह काफी माहिर हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर में पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए इन्होंने क़ानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्हें जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाकों की वस्तु स्थिति का अच्छी तरह से ज्ञान है। जयपुर में किस-किस तरह की अपराध की घटनाएं अधिक होती हैं और इन अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा तरीका और उपाय बेस्ट रहेगा, इसकी भी अच्छी नॉलेज है। जयपुर के सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों और जयपुर की ट्रैफिक समस्या और व्यवस्थाओं को भी अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। जयपुर में पुलिस स्टेशन पर नियुक्त सीएलजी मेंबर की भूमिका और उनके आचरण इत्यादि के बारे में इन्हें काफी कुछ जानकारी है, इसलिए जयपुर शहर इनके लिए अनजान शहर नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें जयपुर के करीब 40 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी है। लेकिन पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर विराजमान होने के तुरंत बाद इन्होंने पहले से ही एक्टिव जयपुर पुलिस को और एक्टिव बनाने के लिए जो प्रयास और प्रयोग किए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सचिन मित्तल की जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की यह दूसरी पारी अपराध जगत से जुड़े लोगों लोगों पर काफी भारी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं जयपुर में अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे लोगों को अपना ठिकाना बदलना पड़ सकता है। क्योंकि सचिन मित्तल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने सीएसटी के गठन की प्रक्रिया जोर-जोर से शुरू कर दी है। इसके लिए तमाम तरह के आवश्यक संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं तथा इसमें फोर्स भी बढ़ाई जा रही है, ताकि बड़े से बड़े गैंगस्टर और गुंडा गैंग का सफाया किया जा सके। राहुल प्रकाश खुद एक दबंग आईपीएस अफसर माने जाते हैं, इसलिए सचिन और राहुल इन दोनों इमानदार, कर्मठ और दबंग पुलिस अधिकारियों की जोड़ी जयपुर में न केवल अमन चैन बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है, बल्कि संगठित अपराध गिरोह से जुड़े बदमाशों को इस जोड़ी से घबराकर या तो अपना ठिकाना बदलना पड़ सकता है या फिर उन्हें जेल में जाने को मजबूर होना पड़ सकता है। फिलहाल सचिन मित्तल रोजाना क्षेत्रवार पुलिस के अधिकारियों से मीटिंग लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय और राजस्थान सरकार के विजन को बताने के साथ-साथ उन्हें खुद का विजन भी बता कर जयपुर पुलिसिंग को बेस्ट पुलिसिंग बनाने की दिशा में तेजी से काम करते हुए नजर आ रही है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

साइबर अपराध को रोकने की दिशा में किया उत्कृष्ट कार्य तो मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक

सचिन मित्तल जब एडीजी साइबर क्राइम पद पर नियुक्त थे, तब इन्होंने साइबर क्राइम के मामलों के निस्तारण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया। साइबर अपराध राजस्थान और भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। साइबर क्राइम में हाई प्रोफाइल पढ़ाई किए हुए लोग शामिल हैं, जिन्हें नई टेक्नोलॉजी और संचार माध्यमों की अच्छी जानकारी होती है। जिन्हें इंटरनेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीजों और विषयों की अच्छी जानकारी होती है, जिसके माध्यम से वे साइबर क्राइम घटनाओं को आसानी से अंजाम दे देते हैं। इसके जवाब में राजस्थान पुलिस के पास साइबर अपराधों के मामलों का पर्दाफाश करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारियों की टीम का अभाव है। इसलिए साइबर अपराध के कमान हाथ में लेने के बाद सचिन मित्तल ने पहले राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर क्राइम के अपराध से निपटने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। साइबर क्राइम को रोकने के लिए अलग से विंग बनाकर उसमें टैलेंटेड और अच्छे पढ़े लिखे पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारी को शामिल किया, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और संचार माध्यमों के बारे में बखूबी जानकारी रखते थे। प्रदेश के हर जिले में साइबर अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल पारंगत अधिकारियों पर कर्मचारी की टीम नियुक्त की गई। उसी का परिणाम रहा कि साइबर अपराध के मामलों का पर्दाफाश करने की दिशा में राजस्थान पुलिस तेजी से कार्य करती हुई दिखी। इस पूरे कार्य को सचिन मित्तल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हैंडल किया, जिसका नतीजा यह रहा कि काफी हद तक प्रदेश में उस समय साइबर अपराध की घटनाओं पर अंकुश भी लगा। क्योंकि सचिन मित्तल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों का चुन चुन कर निस्तारण किया जा रहा था और दोषी लोगों को पदकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। इसलिए प्रदेश में साइबर क्राइम से जुड़े बदमाशों में घबराहट की स्थिति बन गई थी। इसके बदले सचिन मित्तल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिन मित्तल ने कहा भी है कि साइबर अपराध वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए सतत और निरंतर प्रयासों के अलावा पुलिस के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और संचार माध्यमों को ज्यादा से ज्यादा समझने और जानने की जरूरत है। इसके लिए टेक कंपनी के सहयोग से जयपुर पुलिस को साइबर क्राइम से निपटने के लिए ट्रेंड करने की योजना पर मित्तल काम कर रहे हैं। सचिन मित्तल मैकेनिक इंजीनियरिंग में बी.ई. है और साइकोलॉजी में एम टेक डिग्री धारी है, इसलिए साइबर क्राइम के जटिल से जटिल मामलों को भी सुलझाने में इन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस तरह के मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और गाइडेंस करते रहते हैं।

कई जिलों के एसपी रहे और फील्ड पोस्टिंग में बिताया लंबा समय

सचिन मित्तल 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शुरू में इन्होंने भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर कार्य किया। इन्हें अपनी आईपीएस की नौकरी में शुरू में ही भरतपुर जैसे जिले में काम करने को मिला, जहां अपराध की घटनाएं अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा होती है। इसलिए सर्विस के शुरू में ही इनका बड़े-बड़े बदमाशों और डकैतों से सामना हुआ, जिससे कार्य करने की क्षमता और हौसले में इजाफा हुआ और अपराधों को रोकने और अपराधियों के बारे में नए-नए अनुभव भी हासिल हुए। इसके बाद इन्होनें झुंझुनू, झालावाड़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर जिलों के पुलिस अधीक्षक पद पर भी कार्य किया। इसके अलावा जोधपुर के पुलिस कमिश्नर पद पर भी नियुक्त हुए। जहां-जहां इन्हें जिलों में नियुक्ति दी गई, उन जिलों में अपराध की घटनाएं अन्य जिलों की तुलना में शुरू से ही ज्यादा होती रही है। इसलिए इनकी दबंग छवि और बदमाशों से निपटने की इनकी पुलिस की कार्य योजना की तैयारी हमेशा शानदार रही, जिसकी वजह से जिस भी जिले में पोस्टेड रहे वहां की जनता ने इनके कार्यों को और वर्किंग स्टाइल को खूब पसंद किया। इन्होंने पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने, पीड़ितों को राहत दिलाने और पुलिस की जांचों को सही समय पर पारदर्शी ढंग से संपन्न करने और दोषी लोगों को सजा दिलाने जैसे कार्यों पर बारीकी से नजर रखी। जिसकी वजह से जिस भी जिले में रहे वहां के पुलिस थानों की कार्यशैली और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार में भी अच्छा सुधार हुआ। कई जिलों में एसपी पद पर अच्छा कार्य करने से प्रदेश की सरकारों ने भी इन्हें ज्यादा फील्ड पोस्टिंग दी, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और पुलिस थानों के कार्य प्रणाली में सुधार हो। अधिक समय तक फील्ड पोस्टिंग मिलने की वजह से इनकी वर्किंग पॉवर, निर्णय लेने की क्षमता और पुलिसिंग के अनुभव में लगातार बढ़ोतरी होती रही। जो आदमी जितना फील्ड में रहेगा वह उतना ही बुद्धिमान और अनुभवी होगा, खासतौर से पुलिस विभाग में जिसकी जितनी फील्ड पोस्टिंग होती है उसका अनुभव उतना ही बढ़ता जाता है। यही सचिन मित्तल के साथ हुआ। प्रदेश में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की, हर सरकारों ने इनके कई जिलों में एसपी पद पर अच्छे काम करने की वजह से इन्हें ज्यादा से ज्यादा फील्ड पोस्टिंग देना ही मुनासिब समझा, ताकि लोगों की ज्यादा भलाई हो और पुलिस थानों के कार्यों में भी सुधार हो। अब जयपुर जैसे शहर में जहां बड़ी संख्या में पुलिस थाने हैं, जयपुर आबादी और विस्तार की तुलना में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो, वायु, सड़क, रेल परिवहन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों के होने से यहां संगठित अपराध की गुंजाइश ज्यादा रहती है। इसलिए भजनलाल सरकार ने जोसेफ के बाद सचिन मित्तल को कमिश्नर बनाना इसलिए जरूरी समझा कि मित्तल के पास फील्ड पोस्टिंग का अपार अनुभव है। इसके अलावा साइबर क्राइम के मामलों को सुलझाने में माहिर हैं, किसी के पॉलीटिकल प्रेशर में भी नहीं आते और ईमानदारी से अपना वर्क करते हैं। इन सब खासियतों की वजह से ही भजनलाल सरकार ने सचिन मित्तल को कमिश्नर पद की जिम्मेदारी देना जरूरी समझा।

जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने के प्रयासों में पूरी ताकत से जुटे हैं नए पुलिस कमिश्नर

जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था शुरू से ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती रही है। जयपुर की आबादी और विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में नई-नई कॉलोनी का विकसित होना, नए-नए चौराहों का डेवलप होना, नई-नई सड़कों का निर्माण होना और फिर हर साल बड़ी संख्या में नए वाहनों का सड़क पर आ जाना, यह तमाम वजह है जिनकी वजह से जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था जयपुर पुलिस के लिए जी का जंजाल बनी रहती है। जयपुर के परकोटे के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई बार बड़े-बड़े प्रयोग किए गए। नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन सब ने समन्वित रूप से कई बार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सामूहिक मंथन किया। मंथन के बाद कई निर्णय भी लिए। जयपुर में कई जगहों पर ओवरब्रिज और हाईवे पुल का निर्माण भी, अंडरग्राउंड ब्रिज और रास्ते भी बनाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक तरह से सुधर नहीं पा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट हर तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत और इसके सुधार में जुटा रहता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो पाई है। सचिन मित्तल अब नए तरीकों और नए प्रयोगों के आधार पर ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के कार्यों को गति देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त को जयपुर के चार चौराहों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। यह वह चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है। इन चौराहों पर यातायात के नियमों का लोग ज्यादा से ज्यादा पालन करें, इसके लिए ट्रैफिक उपायुक्त को यहां पर विशेष तौर पर गौर करके काम करने को कहा गया है। इसके अलावा सचिन मित्तल ने चारों पुलिस उपायुक्त को अपने-अपने इलाके में एक व्यस्त रोड का चयन करके वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल के कार्यों को निरंतर गति देने को कहा गया है। इसके लिए संबंधित थाने को भी इस ट्रैफिक व्यवस्था से जोड़ने को कहा गया है। पिछले दिनों हरमाड़ा में हुए भयानक हादसे के बाद मित्तल जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर और ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इसके लिए जयपुर की बाहर की कॉलोनी में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संबंधित थानों को निर्देशित किया गया है। चाहे परिवहन विभाग कार्रवाई करें या ना करें, नए पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस और संबंधित थाना पुलिस को निर्देशित किया है कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसके जवाब में हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने बड़े स्तर पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। यह कार्रवाई अब निरंतर सतत रूप से जारी रहेगी। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब नियमित रूप से नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, ताकि समय-समय पर जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा होती रहे और जो-जो कमियां और जो-जो सुधार की आवश्यकता सामूहिक मंथन में निकलकर सामने आते हैं, उन पर आवश्यक निर्णय लेकर तुरंत अमल में लाया जा सके।

भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने वाले परफेक्ट अधिकारी हैं सचिन मित्तल

भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान कैडर के अधिकारियों में सचिन मित्तल की ईमानदार पुलिस अधिकारियों में गिनती होती है। अब तक की उनकी लंबी बेदाग आईपीएस की नौकरी में इन्होंने प्रदेश में कई जिलों में पुलिस अधीक्षक और कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। लेकिन चाहे फील्ड पोस्टिंग हो या फिर पुलिस मुख्यालय में बैठकर सरकारी कार्य निपटने की बात हो, अब तक एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब किसी ने भी मित्तल की कार्यशैली, उनके व्यवहार और ईमानदारी पर सवाल खड़े किए। जबकि देखने में यह आया मित्तल जिन-जिन जिलों में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात रहे, वहां उन्होंने जिलों के पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए कि कहीं से भी अगर किसी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की बात आए, तो तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। मित्तल पुलिस की जांचों की प्रक्रिया पर नजर रखते थे और पब्लिक से उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि अगर कोई उनसे रिश्वत मांगे, तो इसकी तुरंत पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक से भी रिक्वेस्ट की थी अपने अनर्गल और अनैतिक कार्य के लिए रिश्वत की पेशकश नहीं करें, अन्यथा रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मित्तल के इस ईमानदार रवैये को देखते ही इन्हें प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान भी दी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजी पद पर रहते हुए उन्होंने प्रदेश भर में भ्रष्टाचारियों और कर्मचारी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था। कई अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा। अब जयपुर पुलिस की कमान हाथ में आने के बाद प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि मित्तल अपने व्यवहार, कड़क मिजाज और ईमानदार स्वभाव से जयपुर पुलिस की सभी जांचों को ईमानदारी से संपादित करवाने के लिए सतत प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। जयपुर में 70 से अधिक पुलिस स्टेशन है और सचिन मित्तल ने पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद ही जयपुर के सभी पुलिस उपायुक्त को निर्देशित किया कि पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली सभी तरह की जांचों की ईमानदारी से जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सचिन मित्तल की ईमानदारी से काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्हें जयपुर जैसे बड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण शहर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की मामूली शिकायत भी सामने नहीं आई है। भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार को लेकर अनर्गल तरीके की बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की एक भी कोई लिखित शिकायत कहीं पर भी दर्ज नहीं हुई है और ना ही भजनलाल सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के किसी भी तरह कोई आरोप लगे हैं। इसलिए प्रदेश की भजनलाल सरकार के ईमानदारी से काम करने की चर्चा पूरे देश में है। इस स्थिति में जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल भी भजनलाल सरकार के भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम करने के रूप में एक परफेक्ट अधिकारी नजर आ रहे हैं।

शहर की आबादी के हिसाब से पुलिस के जवानों व अधिकारियों की भारी कमी

जयपुर शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है, तेजी से आबादी बढ़ रही है। देश के कई राज्यों के लोगों का जयपुर स्थाई रूप से रहने का स्थान बन गया है। सड़क, रेल और वायु परिवहन के साधनों का लगातार विस्तार हो रहा है। जयपुर अब पूरी तरह से मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर तेजी से विकसित हो रहा है। जयपुर में 70 से ज्यादा पुलिस स्टेशन हैं। यहां बड़ी संख्या में देश और विदेश के पर्यटक हर साल घूमने आते हैं। जयपुर सालों से दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके अलावा साइबर अपराध के मामले अन्य राज्यों की तरह राजस्थान और जयपुर में भी खूब हो रहे हैं। जयपुर संवेदनशील शहर माना जाता है, ऐसे में जयपुर शहर की आबादी और विस्तार को देखते हुए यहां जयपुर पुलिस के पास जवानों और अधिकारियों की काफी कमी है। इसके अलावा आवश्यक संसाधन, यंत्र और उपकरणों की भी भारी कमी है। इस बात को पुलिस मुख्यालय में तैनात बड़े पुलिस अधिकारी भी जानते हैं, राजस्थान सरकार भी जानती है। राजस्थान सरकार भी समय-समय पर पुलिस कांस्टेबल और अन्य पदों के लिए भर्ती निकाल रही है। जयपुर पुलिस में अब महिला महिला कांस्टेबल और अधिकारी भी नजर आने लगी है। सत्य बात यह भी है कि जयपुर पुलिस में अधिकारियों की कमी की वजह से एक-एक अधिकारी के पास कई मामलों की जांच रहती है, जिसकी वजह से वह निर्धारित समय पर जांच को कंप्लीट नहीं कर पाता। इसके अलावा जयपुर में राजस्थान विधानसभा भी है। जयपुर में शासन सचिवालय, हाई कोर्ट जैसे कई बड़े संस्थान हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जयपुर पुलिस की होती है। जयपुर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जयपुर पुलिस की होती है। जयपुर में रोजाना देश और दुनिया भर के राजनेताओं और विशिष्ट लोगों के आने-जाने का सिलसिला बना रहता है, इन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जयपुर पुलिस की होती है। इन तमाम बातों को देखते हुए जयपुर पुलिस के पास जो संसाधन मौजूद हैं, वह काफी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को साफ कहा है कि कम संसाधन होने का हवाला देकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड सकते। हमें कम संसाधन में भी बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि जयपुर की जनता की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर ही है। हालांकि नए पुलिस कमिश्नर पुलिस मुख्यालय और राजस्थान सरकार को जवानों, पुलिस अधिकारियों और संसाधनों की कमी के बारे में भी अवगत करवा रहे हैं।

थानों की कार्यप्रणाली और पुलिस कर्मियों के अच्छे व्यवहार को लेकर गंभीर और चौकस है सचिन मित्तल

सचिन मित्तल काफी अनुभवी आईपीएस है और यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पुलिस थानों की कार्य प्रणाली मजबूत और अच्छी हो तथा थानों में नियुक्त पुलिस कर्मियों का व्यवहार जनता के प्रति दोस्ताना हो, तो पुलिस का आधे से ज्यादा काम अपने आप ही सरल और आसान हो जाता है। इसलिए कमिश्नर पद पर नियुक्त होने के बाद सचिन मित्तल का पूरा फोकस शहर के पुलिस थानों की कार्यशैली पर टिका हुआ है। हालांकि इससे पहले के पुलिस कमिश्नर जोसेफ की ओर से भी थानों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे, कई नवाचार किए थे जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए थे। जो सब खुद महीने में दो थानों में जाकर जनता दरबार लगाया करते थे और लोगों की समस्या सुना करते थे। इसलिए जयपुर के पुलिस थानों में बदलाव की जो प्रक्रिया है वह निरंतर अब भी जारी है। सचिन मित्तल का फोकस बीट व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तरफ है तथा सीएलजी मेंबर की नियुक्ति पारदर्शी और ईमानदार तरीके से हो। इसके लिए आने वाले दिनों में सीएलजी मेंबरों की नियुक्ति के लिए कुछ और कठोर गाइडलाइन निर्धारित की जा सकती है। प्रत्येक पीड़ित की रिपोर्ट और शिकायत को हर हाल में दर्ज किया जाए और प्रत्येक मामले की जांच निश्चित समय में ईमानदारी से पूरी की जाए तथा थाना स्तर पर पुलिस की निगरानी के प्रबंध को और मजबूत किया जाए। इसके लिए मित्तल ने सभी पुलिस उपायुक्त को कमिश्नर की कुर्सी पर बैठते ही निर्देशित भी कर दिया था। मित्तल का कहना है कि पीड़ित को पुलिस उपायुक्त और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक आना ही ना पड़े, इसके लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया गया है। थाना इलाके में स्थित होटल, धर्मशाला, मदरसा इत्यादि की रूटीन जांच हो। अधिकारी अपने इलाके में मौजूद लोगों के नियमित संपर्क में रहे और उन्हें इस बात के लिए नियमित रूप से अलर्ट करता रहे कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए, तो उसके बारे में तुरंत उसे या पुलिस स्टेशन को सूचित करें। अगर इस तरह की व्यवस्था हर थाना स्तर पर सुनिश्चित कर दी जाती है, तो फिर पुलिस का आधे से ज्यादा काम अपने आप ही आसान हो जाता है। कुछ इसी आइडिया के साथ सचिन मित्तल जयपुर में पुलिसिंग के काम को गति देने में जुटे हुए हैं।

गैंगस्टर की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पड़ोसी राज्यों के पुलिस के साथ जयपुर पुलिस का बेहतर समन्वय बनाने के प्रयास

अपराध जगत से जुड़े लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बना हुआ है, जिसमें एक प्रदेश के गुंडा गैंग की दोस्ती दूसरे प्रदेश के गुंडा गैंग से बनी हुई है। इसलिए वारदात तो अंजाम देने के बाद किसी अन्य स्टेट में जाकर अपने संपर्क में रहने वाले बदमाशों के ठिकानों पर जाकर शरण ले लेते हैं। इसी तरह से अन्य राज्यों में अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे प्रदेश के बदमाश राजस्थान में आकर यहां अपने दोस्त बदमाशों के ठिकानों पर छुप जाते हैं। दो अलग-अलग स्टेटस के बदमाशों की यह दोस्ती पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती है। इसको संगठित अपराध गिरोह से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए जयपुर पुलिस कमिश्नर पहले से ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाए हुए हैं। समय-समय पर विभिन्न पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ जयपुर पुलिस प्रमुख गैंगस्टर और गैंग के सदस्यों की लोकेशन और गतिविधियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करती रहती है। सचिन मित्तल पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्य में एंटी टेररिस्ट फोर्स और खुफिया तंत्र के साथ मिलकर संगठित अपराधों की कमर तोड़ने की कोशिश में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, ताकि जयपुर में दूसरे राज्यों के अपराधियों को शरण ना मिल सके। उनकी लोकेशन और उनकी गतिविधियों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। जयपुर में सभी पुलिस थाना अधिकारियों को इस बात के लिए अलर्ट रखा गया है कि उनके इलाके में उनकी यह जिम्मेदारी है कि कोई बाहर का बदमाश आकर शरण ना ले सके। इसके लिए प्रत्येक थाना स्तर पर सघन चेकिंग अभियान और पुलिस के दिन और रात्रि कालीन गस्त को भी और मजबूत करने की दिशा निर्देश नए पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए हैं।

जयपुर पुलिस के खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे मित्तल

जानकार लोगों का कहना है कि सचिन मित्तल पुलिसिंग में नवाचारों को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रहे हैं। वह यह जानते हैं कि वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग में अपराधी ताकत के बल पर नहीं, बल्कि अपने चतुर दिमाग के दम पर वारदातों को ज्यादा अंजाम दे रहे हैं। अब अपराध जगत से अच्छी-अच्छी हाई प्रोफाइल पढ़ाई करने वाले युवा जो मौज मस्ती और कम समय में करोड़पति बनने की तमन्ना से जुड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस इन चतुर दिमाग के टैलेंटेड बदमाशों से चतुराई और बुद्धिमत्ता से ही निपट सकती है। इसके लिए जरूरी यह भी है कि पुलिस कर्मियों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें पर्याप्त तरह के आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा पुलिस का खुफिया तंत्र जितना मजबूत होगा, उतना ही चतुर दिमाग के अपराधियों को अपराध करने से पहले ही पुलिस पकड़ भी सकती है। इसलिए जयपुर पुलिस अब अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ इसका विस्तार कर रही है। खुफिया तंत्र को तमाम तरह के आधुनिक उपकरण और यंत्र दिलाने की दिशा में भी नए पुलिस कमिश्नर काम करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में बम धमाके के बाद जिस तरह से कई डॉक्टरों के आतंकी होने की बात सामने आई, उसके बाद पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ जयपुर पुलिस भी अब अपने स्तर पर एक बेजोड़ नेटवर्क के आधार पर निरंतर सतत रूप से कार्य करते हुए उन लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके साथ-साथ संगठित अपराध गिरोह से जुड़े बदमाशों को चिन्हित करने और उनकी लोकेशन का पता लगाकर उन तक पहुंचने की दिशा में भी जयपुर पुलिस का खुफिया तंत्र तेजी से गुपचुप में अपना कार्य कर रहा है। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का कहना है कि खुफिया तंत्र के मजबूत और विकसित रहने से अपराध से पहले ही अपराधियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिसकी वजह से अपराध की घटना होगी ही नहीं। इसलिए जयपुर में खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में मित्तल बारीकी से और गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।

जयपुर से जुड़े सभी राजमार्गों पर स्थित पुलिस की चेक पोस्ट को अत्याधुनिक हथियार और उपकरण से सुसज्जित करने के प्रयास

जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा, जयपुर-कोटा, जयपुर-अजमेर जैसे बड़े सड़क मार्ग पर पुलिस की चेक पोस्ट बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अब भी आधुनिक हथियार और उपकरण की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल छोटे से छोटे बदमाश के पास भी विदेशी हथियार मिलना आम है। ऐसा कई बार देखने को भी मिला है, जब आधुनिक हथियारों से सुसज्जित बदमाश पुलिस को चकमा देकर या फिर उनका मुकाबला करके फरार हो जाते हैं। इसलिए जयपुर की सभी पुलिस चेक पोस्ट पर विशेष रूप से प्रशिक्षण हासिल किए हुए जवानों और पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने की दिशा में कमिश्नर मित्तल काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की चेक पोस्ट को आधुनिक हथियार और उपकरण से भी सुसज्जित किया जाने युद्ध स्तर पर कमिश्नर की ओर से प्रयास किया जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय और राजस्थान सरकार से आवश्यक संसाधन की डिमांड भी की जा रही है।

शहर के मकान मालिकों को किरायेदारों के सत्यापन के लिए और अलर्ट करने की सचिन मित्तल की तैयारी

जयपुर में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग यहां नौकरी और मजदूरी के लिए आए हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों से हजारों की संख्या में यहां लोग नौकरी और मजदूरी के लिए आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में यहां लोग ज्वेलरी, नगीना इत्यादि कार्यों में जुटे हुए हैं। लाखों की संख्या में यहां पश्चिम बंगाल के आए लोग जयपुर के चार दिवारी इलाकों के जयपुर के बाहरी इलाकों में भी परिवार सहित रहने लगे हैं। इसी तरह से बिहार और मध्य प्रदेश से भी मजदूरी करने यहां बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। इन लोगों का जयपुर में आना-जाना लगा रहता है, इसलिए कई बार अन्य राज्यों में वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अपने यहां परिचित लोगों के पास जाकर छुप जाते हैं। कई बार इनके परिचित लोगों को भी अंदाजा नहीं रहता कि यह लोग वारदात को अंजाम देकर उनके पास शरण के लिए आए हैं। इसलिए जयपुर पुलिस अब किराएदारों के सत्यापन के कार्य को कड़ाई से लागू करने की और तेजी से कार्य कर रही है। सचिन मित्तल की ओर से प्रदेश के सभी पुलिस उपायुक्तों निर्देशित भी किया है कि वह अपने-अपने इलाकों में बाहर से आए लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें। मकान मालिकों को हर हाल में किराएदारों का सत्यापन करवाने की बात भी कही है। यह सत्य बात है कि बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से मजदूरी करने आए लोग अधिकांश शराब पीने के आदि भी होते हैं, इसलिए उनसे कई बार शराब के नशे में अनैतिक और अनाचार गतिविधियां भी हो जाती है। कई बार शहर में चोरी, नक बजनी जैसी वारदातों में कई बार बाहर से लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। इसके अलावा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों पर भी जयपुर पुलिस को नए पुलिस कमिश्नर मित्तल ने अलर्ट किया है। इसके लिए जयपुर के विधायक बालमुकुंद आचार्य कई बार राजस्थान विधानसभा और राजस्थान विधानसभा के बाहर भी क्लियर कर चुके हैं कि जयपुर में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों और आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल हैं। इसलिए मित्तल ने जयपुर के सभी पुलिस उपायुक्त को संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है।

सचिन मित्तल जानते हैं जयपुर आतंकवादी संगठनों के निशाने पर है, 24 घंटे जयपुर पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश

पिछले दिनों जयपुर में बम ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसी की जांच में जो नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं, डॉक्टर के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। जयपुर में वर्ष 2008 में सिलसिलेवार बम विस्फोट का दर्द जयपुर के लोग अब तक नहीं भूले हैं। इन सब तथ्यों से पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए मित्तल ने जयपुर पुलिस के दिन और रात की चौकस को और मजबूत करने के निर्देश शहर के सभी पुलिस उपायुक्त को दिए हैं। बीट अधिकारी को अपने-अपने इलाके में नियमित रूप से निगरानी करने और स्थानीय लोगों के संपर्क में रहकर संदिग्ध लोगों पर नजर रखने को कहा है। जयपुर में होटल, गेस्ट रूम, मदरसा, धर्मशाला सब जगह पर रोजाना पुलिस अधिकारियों को मौके पर जाकर ठहरे हुए लोगों की जांच पड़ताल करने को कहा गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जयपुर एयरपोर्ट इत्यादि सभी जगह पर जयपुर पुलिस की खुफिया शाखा के अधिकारियों को निगरानी के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा। जयपुर के आसपास विभिन्न सड़क मार्गों पर स्थित बड़े फार्म हाउस इत्यादि सभी जगह पर पुलिस को नजर रखने को कहा गया है। इन सब विषयों पर मित्तल खुद नियमित रूप से पुलिस उपायुक्त से अपडेट लेने के अलावा थाना स्तर पर भी जरूरत पड़ने पर बातचीत करके पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं। क्योंकि जयपुर काफी व्यस्त और दौड़ धूप वाला शहर माना जाता है। जयपुर के कई इलाके काफी तंग और भीड़ भरे इलाके हैं जिन पर आतंकवादी संगठनों की निगाह रहती है, इसलिए पुलिस को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को सुनिश्चित किया गया है। मित्तल जानते हैं कि पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही जयपुर में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इसलिए पुलिस कमिश्नर मित्तल ने अलग-अलग तरह से अलग-अलग तरीकों से जयपुर पुलिस की जिम्मेदारी निर्धारित की हुई है।

राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए मान्यता प्राप्त

जयपुर टाइम्स

(जयपुर एवं चूरू से एक साथ प्रकाशित)

जयपुर टाइम्स

भजनलाल सरकार में वीआईपी कल्चर का त्याग करने वाले पहले मंत्री "संजय शर्मा"

जयपुर टाइम्स

राजनीति में दादी से आगे निकली दिया कुमारी

दिया कुमारी ने अब तक तीन चुनाव लड़े और तीनों जीते

जयपुर टाइम्स

किसान और पशुपालकों में ओम पूनिया की लोकप्रियता चरम पर

सामाजिक सरोकारों के कामों में भी पूनिया की संत - महात्मा जैसी भूमिका

जयपुर टाइम्स

पहले वाजपेई का अब नरेंद्र मोदी का दिल जीता "अश्विनी वैष्णव" ने

जयपुर टाइम्स

पिता के सपनों को साकार कर रहे झाबर सिंह खर्रा, शहरों को नया लुक देने के लिए कर रहे है कड़ी मेहनत

जयपुर टाइम्स

भजनलाल शर्मा ने रचा इतिहास, डेढ़ लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संग मनाया "रक्षाबंधन"

जयपुर टाइम्स समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ने के लिए क्लिक करें

www.jaipurtimes.org

https://www.youtube.com/@JaipurTimes

@JaipurTimes2

@jaipurtimes.news

जयपुर टाइम्स में संवाददाता बनने के लिए, विज्ञापन एवं समाचार प्रकाशित करवाने के लिए सम्पर्क करें :-

Email- jaipurtimes2007@gmail.com (समाचारों के लिए)

Email- jaipurtimes.adv@gmail.com (विज्ञापनों के लिए)

मो. 7014217770

प्रधान कार्यालय- सी 588, 4सी स्कीम, न्यू लोहा मण्डी रोड़, रोड़ नं. 14, सीकर रोड़, जयपुर (राजस्थान)